

कश्मीर की मुंडकोल झील : कुदरती चमत्कार

दिल्ली की सुबहें हमेशा किसी अदृश्य हलचल से भरी होती हैं। एक शहर जो नींद से अधिक अपनी गति पर विश्वास करता है। लेकिन उस सुबह, जब मैं मुंडकाल झील के लिए निकल रहा था, दिल्ली मुझे अनायास शांत लगी, मानो वह भी जानती हो कि मैं कुछ और गहरे, और अधिक निर्मल संसार की ओर जा रहा हूँ। अवद्वर्क की हल्की ठंड थी और परंपराओं की भीड़ अपनी रोजमर्रा की बेचैनियाँ ओढ़े हुए थी। मैं उन भीड़ों से निकलकर एक ऐसी जगह जाने वाला था, जहाँ भीड़ केवल असमान की होती है— बदलों की, सितारों की, और दूर खड़े पहाड़ों की।

प्लाइट न जैसै ही कश्मीर की घाटियों के ऊपर मंडराना शुरू किया, इन्डिका के बाहर का दृश्य किसी उत्तम चित्रकार की कृची जैसा दिखने लगा। पहाड़ों की नीली धारियाँ, झीलों का कांच-सा फैलाव और बर्फ की चादरों पर सूर्य की पहली किरणें- वह सब कुछ ऐसा था, जैसे किसी अधूरी कविता में मैं अचानक एक पूर्ण विराम बनकर उतर रहा हूँ। श्रीनगर एयरपोर्ट अपेक्षाकृत शांत था, पर हवा में वह परिचित कश्मीरी खुशबू थी- सेब, पाइन और न जाने किस पुराने समय की कोई स्मृति।

शहर की ओर जाते हुए डल झील सामने आई— सड़क के किनारे-किनारे चलती हुई, जैसे शहर का आधा प्रतिबिंब हर समय अपने साथ लेकर चलती हो। शिकारे (विशिष्ट नाव) सुबह की धूप में धीमे-धीमे हिल रहे थे और पानी पर गिरती रोशनी ऐसे चमकती थी, जैसे किसी ने झील पर मोहन सोना बिखेर दिया हो। मैं अपने होटल 'जीलान रिट्रीट' पहुँचा, जो डल के किनारे एक शांत कोने में था। लकड़ी के कमरे की खुशबू और शिफ्टी से दिखती झील ने मन को तुरंत ठंडा कर दिया। लंच में कश्मीरी राजमा, हक और गर्म-गर्म चावल मिले। कश्मीरी से परिचय वहीं से शुरू हुआ, जहाँ भोजन सरल हो और आत्मा को छुले।

शाम ढलते-ढलते मैं शंकराचार्य पहाड़ी पर पहुँचा। श्रीनगर शहर नीचे रोशनी की बूँदों में बदल रहा था, और झीलें उन रोशनियों को किसी सावधान दर्पण की तरह पकड़कर झिलमिला रही थीं। रात को होटल वापस लौटा और सोने से पहले एक बार फिर झील की शांति को खिड़की से देखा। अगले

मीर की मुंडकोल झील : कुदरती

दिन मैं हरमुख पर्वत की गोद में बसे मुंडकोल झील की यात्रा पर जाने वाला था। मन में एक अनकही उत्सुकता थी।

श्रीनगर से सोनमर्ग और वहां से मुंडकोल की चढ़ाई। सुबह पांच बजे का श्रीनगर किसी उपन्यास की धीमी शुरुआत की तरह होता है- खामोशी, नम और उम्मीदों से भरा। टैक्सि मुझे सोनमर्ग ले जाने के लिए तैयार खड़ी थीं। रास्ता सिंध घाटी से होकर जाता है- उन पहाड़ों से, जिनके बीच से यह नदी चांदी की तरह बहती है। जुनदे (झावर) रास्ते भर कश्मीर की



1. हमें अपना फीडबैक, सुझाव या टिप्पणियां देने के लिए दिए गए बार कोड को स्कैन करें या मेल करें।
2. आप हमें अपनी रचनाएं, कविता या आलेख भी भेज सकते हैं। जिसे हम अपने आने वाले अंक पर प्रकाशित करेंगे।

Email- thephotonnewsjharkhand@gmail.com

कहानियां सुनाता रहा- कौन-सी बर्फ. कहां गिरती है, कौन-सी घाटी कब

खुलती है, कहां के चरवाहे किस मौसम में लौटते हैं। मैं उसकी आवाज में कश्मीर की मिट्टी का अपनापन सुन रहा था।

लगभग तीन घंटे बाद हम सोनमर्ग पहुँचे— सुनहरी घासों की घाटी, जिसे 'मैदा का सोना' कहें तो गलत नहीं होगा। वहाँ से ट्रेक शुरू होता था। हमें ठंड थी, पर सूरज की किरणें उस संतुलित कर रही थीं। बैकपैक कंधों पर डाला और हनुमुख पर्वत की दिशा में कदम बढ़ाए। रास्ता पहले घास के मैदानों से शुरू होता है, फिर धीरे-धीरे पाइन के जंगलों में दाखिल हो जाता है।

गरमाहट लाने वाली 'कहवा'

झील के किनारे बैठते ही समय जैसे
 टहर गया। पानी में आकाश
 प्रतिबिम्बित था और बादल उसमें
 डूबते-उभरते प्रतीत हो रहे थे।
 दोपहर को गाइड ने कश्मीरी चाय
 'केशवा' बनाई। इलायची, दालचीनी,
 केसर और बादाम की खुशबू ने उस
 ढंड में आत्मा तक को गर्म कर
 दिया। आसपास कुछ ट्रैक्टर थे, जो
 तबू लगा रहे थे। सबके चेहरों पर
 वही भाव था। प्रकृति के सामने
 असीम छोटा होने का। शाम को सूर्य
 डूबने-झील के उस किनारे पर
 उतरने लगा, जहां से चोटियां सोने
 की लकीरों से चमक उठीं। पानी में
 पड़ती उस सुनहरी आभा ने मानो
 झील को पिघला हुआ सोना बना
 दिया। पर्वतीय सुरक्षा का अपना ही
 धर्म होता है। वह बिना कोई आवाज
 किए संसार को बदल देता है। मैं देर
 तक उसकी ओर देखाता रहा, सोचता
 रहा कि इस क्षण को शब्द कभी पुराना
 नहीं कह पाएंगे। रात को तू में
 सोना एक अनुभव था। हवा बाहर
 सीटी बजाती, दूर कहीं ग्लेशियर की
 बर्फ टूटने की आवाज आती, और
 ऊपर आकाश अनगिनत तारों का
 घर था। कश्मीर का पहाड़ी आकाश
 जैसे अपनी पूरी ज्योति पृथ्वी पर
 उड़ेल देता है। नींद टूट-टूट कर
 आती रही, पर हर बार आकाश की
 ओर देखकर लगता कि यही जागना
 इस यात्रा का सबसे कीमती हिस्सा
 है। सुबह की रोशनी मुंडको झील
 पर किसी चमकाता की तरह उतरती
 है। पानी रात की ढंड से हल्का
 धुंधलाया होता है और जैसे ही सूरज
 की पहली किरण पड़ती है, वह नीले
 रंग की एक गहरी सांस लेकर
 चमक उठता है। मैंने झील से विदाई
 लेने से पहले उसके किनारे थोड़ी
 देर अकेले बिताई। वह वह समय

था, जब मैं किसी अनकहे संवाद में लगा रहता है। प्रकृति से, बीते दिनों से, और खुद से। वापसी सोनमर्ग तक उसी कतिन नहीं थी। उतरते समय रास्तों के रंग बदल गए थे। घास पर हल्की ओस, पाइन पहाड़ों से गिरती रोशनी और दूर पहाड़ों के पीछे बाज की उड़ान। सोनमर्ग पहुंचकर मैंने स्थानीय ढाबे में गर्म हहरोज (कश्मीरी दाल), उबलते चावल और ताजी रोटी खाई। सरल भोजन हमेशा पहाड़ों में किसी उत्सव की तरह लगता है। शाम तक मैं श्रीनगर लौट आया। डल झील ने अपनी शाम की नर्म रोशनी में मेरा स्वागत किया। एक विशिष्ट पर पर बैठकर मैं झील के बीच तक गया—नौका पानी को चिरते हुए धीमे-धीमे आगे बढ़ती रही और पहाड़ों की प्रकृष्टियाँ उसके शांत पानी में डोलती रहीं। विशिष्ट वारे ने अपनी धीमी आवाज में कहा, 'साहब, कश्मीर लौटकर आपने वलों की जगह हमेशा वहीं रहती हैं।' मैंने मुखुरता दिया— मुंडकोल झील के नीलेपन ने सचमुच कहीं भीतर कुछ बदल दिया था। रात को सोनमर्ग की तलाश की यात्रा का असली सौंदर्य शायद इस लोटने में ही है— जहां हम शरीर से वापस आते हैं, पर आत्मा का एक टुकड़ा किसी झील, किसी घाटी, किसी पहाड़ पर छोड़ आते हैं। तीन दिन की यात्रा, पर असर वर्षों का। दिल्ली लौटते समय विमान की सिटिडी से बादल नीचे बह रहे थे और मैं सोच रहा था। मुंडकोल झील केवल एक जगह नहीं, एक मौन अनुभव है, एक नीला संवाद है, एक ऐसा क्षण जो अपनी स्मृति में बहुत देर तक चमकता रहता है, जैसे किसी अहोरात्रि में अटका एक अकेला विस्तार।

पत्तियां भी जैसे किसी कांच की प्लेट पर रखी हो।

मुंडकाल झील आखिरकार उस मोड़ के बाद सामने आई, जहां चढ़ाई थोड़ी कठिन हुई थी। दूर से ही उसका नीला विस्तार आंखों को उतर आया। झील चारों ओर वफ़ीली होत-यैसे से घिरी थी और उनमें से किसी ग्लेशियर की धारा चुपचाप इसमें गिर रही थी। एक धीमा संगीत, जो पूरे वातावरण में घुल जाता था। हवा में ठंड थी, लेकिन उसके भीतर एक पवित्र-सी शुद्धता भी थी, जैसे प्रकृति ने अपने सबसे स्वच्छ विचार यहीं रख छोड़े हों।

मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता'।

वो फस पर डफली बजाते रहे और स्त्रुमुम में गाते रहे। जब गाणा-बजाना खत्म आ तो मैंने कहा - 'आप तो बहुत अच्छे होते-बजाते हैं। लेकिन इस सबका कछा क्यादा भी है क्या?' वो झल्ला उठे और बोले 'अबे जंतर-मंतर इतनी डफली बजाने और अपने का एक हजार तक मिल जाता है। मैंने अपनी पत्रकारिता वाली नैकरी छोड़ दी है, सब मैं प्रोलास आन्दोलनजनी हूँ। कभी-कभी तो डूढ़-दो महीने की परफार्मिस का काम का साथ मिल जाता है। लेख लिखता था तो कोई ना पढ़ता था, अब देखो मुझे लोग 'फेस ऑफ प्रोटेस्ट' कहते हैं, समस्या किसान की तो ये नेट्यूरली की, मेरे पास हर विरोध के लिए अलग-अलग टोडआप, गीत और गीत रखी है। कोरोना में मेरी बहुत अच्छी कामदनी हुई। कभी-कभी तो इन सबमें मैं भीमली को भी ले जाता हूँ। बच्चों के तो प्रोटेस्ट में जाने पर डबल भुगतान मिलते हैं। मैंने तो है 'खेला होबे' ये कहकर वो हो-हो रहे हैं।

मैं उनकी बात का कुछ जवाब देना चाहता था, तब तक मेरा मोबाइल बज उठा, फोन थाया तो उधर से श्रीमती जी ने देहाड़ते हुये कहा - 'बिजली का बिल जमा किया था?' मैं झूल गया, कल जमा कर दूंगा।' कल छुट्टी है, बिजली वालों का ऑफिस बंद है।' आज प्रजली वाले आए थे, बिजली काट गए हैं और जमा घड़ी में टाइम देखो क्या बजा है? मैंने बिजली का बिल जमा कर दो और जमा नहीं जमा होता तो बिजली लेकर ही मगर, वरना- ये कहकर उधर से पत्नी ने फोन काट दिया।

मैंने घड़ी देखी, शाम के छह बज चुके थे।
ब्रजली विभाग का आफिस बंद हो चुका होगा।
और कल छुट्टी है। हे भगवान, अब मैं बिजली
का इंतजाम कहाँ से करूँगा?

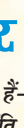
मैंने आरजे का अभिवादन किया, राम-राम कहना चाहता था लेकिन अचानक ध्यान आया और हाथ जोड़ कर निकल पड़ा वे पीछे से मुझे कारते रहे।

मैं बिजली का इंतजाम कहाँ से कैसे करूँगा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि राम मेरी रक्षा करें। नहीं नहीं काली जी, शीतला ता स्त्री शक्ति के कोप से मेरी रक्षा करें, वरना जाने कौन सा मेरे साथ 'खेला होवे'।



कविता





वेवी शॉ

पैर और त्रिवली

पैर और त्रिवली- ये दो
 एक प्राचीन-प्रवीण-रहस्य में ले जाते थे तुम्हें
 इस बार त्रिवली को तुमने छोड़ दिया
 लेकिन पैरों को नहीं
 यात्रागत ये पैर बहुत दूर तक जा रहे थे
 बिना थके, प्रेम से भरे, स्वप्न रचते हुए
 मेरे पैरों से चलकर
 तुम मुझ तक आ गए
 पहुँच गए साधना पर

चिर स्थिर मैं
 पत्थर बन गई
 तुम्हारे गंतव्य पर!

प्यार के रूप

प्यार के दो रूप हैं-
 श्रांति और क्लांति

समय थका हुआ था
 धीरे-धीरे संध्या आ रही थी शहर में
 धीरे-धीरे धुन बदल जा रही थी संध्या-राग में
 धीमी ताल में शामिल होते हुए
 तुम तुम नहीं थे
 मैं मैं नहीं थी
 सिर्फ सारे अंग
 एक दूसरे में खोए हुए
 चिर आनंद के संगम में

टूटा हुआ घर
 गाँव के लिए
 जैसे लौटते हैं
 युद्ध-क्लांत जनपद...

— **त्यंग्य ■ बर्बरीक**

पूर्वी भारत से हमारे राम जय बाबू पथारे। मैंने उनको रोसोगुल्ला देकर कहा- 'राम राम राम जय बाबू।' जय राम बाबू चिहुँक उठे, पसीना-पसीना ही उगे और बोले - 'शुशु से खुद निबटना जानता हूँ मित्र से पर, देव! तुम रक्षा करो।' कविवर दिनकर ने ये लाइनें तुम्हारे जैसे मित्र-शत्रु के लिए ही कही होंगी। सही बात है जब तुम जैसे शुभचिंतक मित्र हों तो शत्रु की क्या जरूरत। ये खेल नालो, लेलो हमसे, रसगुल्ला खिलाओ या ना खिलाओ, लेकिन मेरे नाम के साथ इतने बार राम मत लगाओ, नहीं तो मेरे पीठ की चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। मेरे साथ खेला होबे जातूँ। मैं अब आरजे के नाम से जाना जाता हूँ और राम-राम नहीं बल्कि नोमोस्करम करके ही दुआ-सलाम करता हूँ। उनका पैसी नाम सुनकर मुझे सुखद अचरज हुआ और उनके नाम को लेकर डर, को लेकर थोड़ी हैरानी भी। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा - 'घबराइए मत आप राजधानी में हैं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। वैसे ये खेला होबे क्या है?'

उन्होंने टंडी सांस लेकर कहा - 'आमतौर पर देश के लोग विराट कोहली जैसे लोग से इम्प्रेसशन लेते हैं तो फ्रंट से आकर लड़ें करते हैं और एक अनुकूलणीय मिसाल पेश करते हैं। हर समस्या का सबसे पहले खुद सामना करते हैं। लेकिन, हमारे उधर थोड़ा दिन धोनी नौकरी क्या कर लिया, उधर सब को धोनी स्टायल का लीडरशिप कर रहा। मतलब सब लोग खेल लो, मैं लास्ट में सिर्फ कप उठाने आऊंगा। और सबसे लास्ट में खेलने का फायदा ये है कि जब सब नहीं खेल पाये तो मैं क्यों खेलूँ?' 'ये धोनी -विराट का क्या मतलब, चुनारों से' मैंने जिज्ञासा प्रकट की। 'अभी देखो, विराट सामने से आकर लड़ता है, चुनौती देता है, अब जीते या हारे ये एक बात है, ऐसा एक पार्टी कर रही है। जबकि दूसरी पार्टी धोनी की तरह सो बहाना लिए बैठे हैं मैं कि तुम्हारी नेता तो हैं! लेकिन मुझ पर निश्चर नहीं, खुद लड़ो - उलझो। तुम हारे तो मैं भी हार जाऊंगी और ये सामूहिक जिम्मेदारी होगी और अगर कहीं जीत गए तो इसका क्रेडिट मेरे करिश्माई नेतृत्व को मिलेगा।

अभी से लड़ने के लिए ये अन्तरे याद कर
लो
'कोरबो



दिलीप कुमार

लोड़बो
हारबो रे'
और अगर किसी तिकड़म से जीत गए तो
बताना कि हमारी जीत का श्रेय इन लाइनों को
जाता है

'कोरवो,
लोड़वो
जीतवो रे'
वैसे सुना है किंग खान ने सिर्फ एंथम दी
है, बाकी और कुछ देने से इनकार कर दिया
है। ये दिलचस्प खेल शुरू हो चुका है। जिस
वेब्ट मैनेजमेंट कम्पनी को एक महत्वपूर्ण
चुनाव की कमान सौंपी गई है, उसने खेल शुरू
करने से पहले ही खेल कर दिया। क्योंकि जिस
कम्पनी का मेन स्टाफ पूर्वी भारत में एक दल
को चुनाव जिताने पर लगा है, उसी कंपनी की
सेक्टर कंसर्न ने विरोधी दल के चुनाव जीतने
की भविष्यवाणी कर दी है।

असली खेला तो हो गया, पहले खेला रोबे की चुनौती देकर ललकार दिया गया और फेर खुद को घायल की श्रेणी में डाल दिया। अब खेल तो बराबरी के लोगों के बीच ही होता है।

‘लेकिन ये खेला शुरू होते ही खिलाड़ी के लक्ष्य लक्ष्य होने का सीना है और गोत्र बताने का क्या चकर है’ मैं नहीं सोच जानना चाह।
 ‘आजकल बाबू ने नहरी सांझ की ओर फिर बोले - ‘इवेंट मैनेजमेंट कम्पनी के कर्ता-धर्ता अंग्रेजी में बोलाते हैं लेकिन हैं जमीन से जुड़े किसान। हमारे देश में बहुत से विविधभाषा हैं। कर्ता-धर्ता ही जैसे भारत की नई नरेशरेशन और कर्ता-धर्ता के लोगों को हमारे धार्मिक ग्रंथों को समझाने वाले एक अंग्रेज दल लेखक जब

'खेला होबे'



इसलिए जाते हैं तब अपने खाने में गाव के खून से बनी हुई डिश को सहर्ष पेश करते हैं। इस बात के बड़े दूरगामी नतीजे हैं। मसलन कुछ बरस पहले भारत में जब पेप्सी में पेस्टिसाइड होने के सन्देह का बहुत हल्ला मचा था और तब शाहरुख खान उसके ब्रांड अम्बेसडर थे, लोगों ने उनसे पेप्सी ब्रांड को प्रोमोट करना करने की अपील की, तो शाहरुख खान साहब ने कहा कि अगर भारत में पेप्सी पर प्रतिबंध लग गया तो वो अमेरिका में जाकर पेप्सी पीएंगे। पेप्सी के प्रति उनका निश्चल कनिक्शन देखकर मेरी आंखों में आंस आ गए थे।

मैंने उनको टोका - 'लेकिन शाहरूख खान की परमात्रादारी आजकल निजाम गुटखा के साथ है, जबकि सुना है निजी जीवन में वो गुटखा नहीं खाते।' आरजे ने मुझे समझाया 'तुम तो विराट कोहली के टॉस की तरह हो, जो मैच भले जीत जाए लेकिन टॉस जरूर हारेंगे।' और भाई, जब हिंदुत्व की सभी शक्तिशाली ताकतों का शत-प्रतिशत पालन करने के बाद कोई लीडर पब्लिक डोमेन में आकर हिन्दू विरोध की मन्मानी परिभाषा गढ़ कर व्याख्या कर सकता है तो विमल पान मसाला के लिए अजय देवगन और शाहरूख खान अपनी पुरानी और स्थायी दुश्मनी भुलाकर एक नहीं हो सकते? आखिर परदेस में इन दोनों को राष्ट्रीयता सिखाने और दिखाने के लिये विमल पान मसाला से बेहतर वया विकल्प हो सकता है।

मुझे उनकी बात समीचीन नहीं लगी, मैंने कहा- 'इससे कॉमन मेंने के जीवन पर क्या नुक़्स पड़ता है कि अजय देवगन या शाहरुख़ ख़ान ठीक सा गुटखा खाते हैं।' आरजे साहब हल्ला उठा - 'फिर सौ करोड़ के कलेक्शन परगरेट की बातों पर कॉमन मेंने कोई हल्ला काटा रहा है। तीन सौ की एचएमटी घड़ी भी तो मजबूत बताती थी, वो बंद क्यों हो पाई? टैंग ह्युरर की डेड खान की घड़ी कॉमन मेंने क्यों ख़रीदता है? ईएमआई पर, इसीलिए ना कि शाहरुख़ ख़ान उसको पहनता है ना। पढ़ाई-लिखाई में ऋतिक रोशन काफी हल्टे-पुल्टे, ज़्यादातर समय न्यूय़ॉर्क सिख़ने के अभ्यास में लगाया करते थे, लेकिन अब सभी को बता रहे हैं कि फ़लों एप्ले से पढ़ लो तो पणित ना सिर्फ़ जान जाओगे बल्कि दूसरों को पणित भी लगोगे, वे अपने पिता की कम्पनी पार्टनर थे। आजकल हर माता-पिता को एपल पणुगान से अभिवादन से पार्टनर बना रहे हैं। आमिर ख़ान ने दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, अब बेचारे पानी पीचाने के तरीक़े सिख़ने और बताने तुर्की तक जाते हैं। क्या-क्या बताएं होना। यही सब तो खेला होबे है और फिर तो हाथ से ही फ़र्श बजाकर डफ़ली की ताल टोछाव गाने लगे -

'दीप जिसका महल्लात ही में जले
चंद लोगों की खुशियों को ले कर चले
वो जो साए में हर मसलहत के पले
ऐसे दस्तूर को, सुब्ह -ए-बे -नूर को

BRIEF NEWS

कड़ाके की ठंड में 13 स्थानों पर नगर परिषद ने जलाए अलाव
BUXAR : लगातार बढ़ रही ठंड ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। खुरह प्रभावित कर दिया है। खुरह स्थानों और फुटाथ पर रहने वाले लोगों को ठंड से बचाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की सर्दी के कारण सुबह और शाम के समय लोग घरों से निकलने में भी हिचकिचा रहे हैं। ठंड से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से नगर परिषद द्वारा शनिवार को शहर के 13 प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई। इन अलावों से आसपास रहने वाले लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है। सिटी प्रबंधक नीरज झा ने बताया कि नाथ बाबा मंदिर, रामरेखा घाट, मॉडल थाना, श्मशान मोड़, बस स्टैंड, ज्योति चौक सहित अन्य स्थानों पर अलाव जलाए गए हैं। हालांकि नगर के विस्तारित क्षेत्रों में अब भी अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।

आरओबी निर्माण कार्य की खामियों को दूर करने की मांग
ARARIA : फारबिसगंज सुभाष चौक पर निर्माण अधीन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान उत्पन्न समस्याओं और उनके निराकरण को लेकर नागरिक संघर्ष समिति की ओर से शनिवार को एसडीओ रंजीत कुमार रंजन को ज्ञापन सौंपा गया। फारबिसगंज अनुमंडल कार्यालय में संघर्ष समिति के अध्यक्ष शाहजहां शाद और सचिव ने तीन बिंदुओं पर एसडीओ का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उनके निराकरण की मांग की। नागरिक संघर्ष समिति ने निर्माण कार्य करा रही एजेंसी संपेदक के द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं सुरक्षा नियमों का समुचित रूप से पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। सैंपे पर गए ज्ञापन में समिति ने बताया कि सर्विस रोड का समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पैदल यात्री एवं छोटे वाहनों को आवागमन में परेशानी होती है।

104 लीटर विदेशी शराब के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार
KATI HAR : जिले के रोशना थाना पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टेम्पू से कुल 104.145 लीटर विदेशी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। रोशना थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि तीन व्यक्ति पश्चिम बंगाल से दो टेम्पो में शराब की खेप लेकर महानंदा चेक पोस्ट की ओर आ रहे हैं। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष ने पुलिस बल के साथ महानंदा चेक पोस्ट के पास पहुंचकर वाहन अभियान चलाया। पुलिस ने बताया कि वहन जाँच के क्रम में तीन व्यक्ति टेम्पू सवार व्यक्ति तेजी से पुलिस बल को देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान सुनील कुमार मंडल, रमण कुमार एवं अमित कुमार यादव के रूप में हुई है।

बीएसईबी की ओर से आयोजित चतुर्थ सक्षमता परीक्षा में 4932 शिक्षक सफल

AGENCY PATNA : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) के अध्यक्ष आनंद किशोर ने शनिवार को नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा (सीटीटी) 2025 के चौथे चरण का परीक्षाफल जारी कर दिया। यह परीक्षा कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित की गई थी। बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि 24 सितंबर से 27 सितंबर 2025, 12 अक्टूबर 2025 और 22 अक्टूबर 2025 को आयोजित इस परीक्षा में कुल 14,936 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल

कुल उत्तीर्णता रही 33.02 प्रतिशत

- परीक्षा कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए की गई थी आयोजित
- सफल घोषित शिक्षकों में 2725 महिला और 2207 पुरुष शिक्षक शामिल

परिणाम देखने के लिए वेबसाइट

परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट <https://sakshamtabihar.com> पर उपलब्ध है, जहां शिक्षक अभ्यर्थी अपने लॉग-इन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं।



14,936 अभ्यर्थी हुए थे शामिल
इस परीक्षा में कुल 8,501 महिला शिक्षक और 6,435 पुरुष शिक्षक शामिल हुए थे। सफल घोषित शिक्षकों में 2,725 महिला शिक्षक और 2,207 पुरुष शिक्षक शामिल हैं। सक्षमता परीक्षा (सीटीटी) 2025 (चतुर्थ) का आयोजन पटना स्थित बापू परीक्षा परिसर के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर किया गया था। प्रत्येक पाली की अवधि 2 घंटे 30 मिनट निर्धारित थी। परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें भाषा से 30, सामान्य अध्ययन से 40 और संबंधित विषय से 80 प्रश्न शामिल थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्पष्ट किया है कि जारी किया गया परीक्षाफल पूरी तरह से औपचारिक (प्रोविजनल) है। परीक्षाफल जारी होने के बाद सभी सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग शिक्षा विभाग द्वारा कराई जाएगी। काउंसिलिंग से संबंधित विस्तृत सूचना शिक्षा विभाग अलग से जारी करेगा।

एसएसपी डॉ. कुमार आशीष बोले- एक करोड़ रुपये मांगने की थी योजना डॉक्टर के साथी ने दी अपहरण की सुपारी, मास्टरमाइंड समेत 7 गिरफ्तार

AGENCY CHAPRA : बिहार के छपरा में प्रसिद्ध डॉक्टर सजल कुमार के अपहरण के असफल प्रयास का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। सारण के एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि इस सनसनीखेज मामले में अब तक सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें मुख्य साजिशकर्ता भी शामिल है। मामले की जांच से पता चला है कि अपहरण की साजिश रचने वाला मुख्य आरोपी डॉ. शिवनारायण सिंह है, जो खुद एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं और डॉ. सजल कुमार के साथ काम करता था। डॉ. शिवनारायण पटना के ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड स्थित बुद्ध कॉलोनी का निवासी है। पुलिस के अनुसार, दोनों डॉक्टरों के बीच जमीन के एक बड़े टुकड़े को लेकर विवाद था, जिसके चलते यह साजिश रची गई।



यह अपहरण की साजिश आंतरिक थी, किसी बाहरी गैंग की नहीं। मुख्य साजिशकर्ता डॉ. सजल कुमार के साथ रहने वाले और काम करने वाले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉ. शिवनारायण सिंह हैं। डॉ. शिवनारायण ने अपराधियों को किराए पर लिया था और लगभग एक करोड़ रुपये की फिरोती मानने की योजना थी।
-डॉ. कुमार आशीष, सारण एसएसपी

इन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य साजिशकर्ता डॉ. शिवनारायण सिंह, हरियाणा निवासी मोटी भारती, गोलू कुमार, धीरज गिरी, रंजन राय, सोनू राय शामिल हैं। एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने इनके पास से दो देसी कट्टा, एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, खोखे और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

पुलिस टीम की रही सराहनीय भूमिका
इस सफल ऑपरेशन में अनुमंडल पुलिस अधिकारी सदर, थाना अध्यक्ष नगर सजीव कुमार, थाना अध्यक्ष भगवान बाजार सुभाष कुमार और जिला सूचना इकाई के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एसएसपी ने टीम की तारीफ करते हुए कहा कि तकनीकी जांच और छापेमारी से मामले का तेजी से खुलासा संभव हुआ। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

बनाई। एसएसपी ने बताया कि फिरोती की राशि करीब एक करोड़ रुपये थी, हालांकि सटीक आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना 17 दिसंबर के रात की है, जब डॉ. सजल कुमार अपने क्लिनिक से घर लौट रहे थे।

पोल से टकरा गई, जिससे वे अफरा-तफरी में फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। जांच में दो अपराधियों गोलू कुमार और रंजन राय को पहले

NEWS BOX

लाइफ सेवियर फाउंडेशन का डाक नुसहरी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

AGENCY ARARIA : फारबिसगंज के डाक नुसहरी शिव मंदिर प्रांगण में लाइफ सेवियर फाउंडेशन की ओर से शनिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने मुफ्त चिकित्सीय परामर्श लिया। चिकित्सीय परामर्श के अनुसार संस्था की ओर से उपलब्ध दवाओं को भी जरूरतमंदों को मुफ्त में दिया गया। शिविर का उद्घाटन विधायक मनोज विश्वास, एसडीओ रंजीत कुमार रंजन, एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा, बीडीओ,बीपीआरओ आदि के द्वारा किया गया। आयोजन में विशेष रूप से प्रखंड प्रमुख ओमप्रकाश पासवान,कारोबारी विजय प्रकाश का सहयोग रहा। चिकित्सक के रूप में डॉ प्रीति प्रभा और डॉ मनीष कुमार दास ने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। मौके पर रंजत रंजन,संस्था के अध्यक्ष मनीष राज, दीपक कुमार, अवतार कुमार, परवेज आलम, सरपंच मनोज मेहता, पिंटू मेहता, मिट्टू, रुबी कुमारी सहित अन्य ग्राणीण मौजूद रहे।

स्कूलों के छात्र-छात्राओं और कर्मियों को एसएसबी ने दिया प्रमाणपत्र

AGENCY ARARIA : जोगबनी में सशस्त्र सीमा बल की 56वीं वाहिनी की ओर से 13 दिसंबर को बॉर्डर यूनिटी रन का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं के अलावे आम जनो ने अपनी भागीदारी दी थी। एसएसबी के बॉर्डर यूनिटी रन में फारबिसगंज के भागकोहलिया में संसालित नोबल एकेडमी की ओर से सफल भागीदारी की गई थी जिसको लेकर एसएसबी की ओर से शनिवार को नोबल एकेडमी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्कूल के प्राचार्य,शिक्षक समेत छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

दो लाख नेपाली करेंसी के साथ यूपी की महिला गिरफ्तार

AGENCY ARARIA : एसएसबी 56वीं वाहिनी की जोगबनी की आई समयार की बॉर्डर चेक पोस्ट कर तैनात जवानों ने एक उत्तरप्रदेश की राने वाली महिला को दो लाख रुपए नेपाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया। जोगबनी के बीसीपी गेट पर भारत-नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 180पीपी 68 के नजदीक भारत साइड में करीबन 20 मीटर की दूरी पर शनिवार को यह गिरफ्तारी हुई। महिला नेपाल से नेपाली करेंसी के साथ नेपाल से भारत में प्रवेश की थी। एसएसबी द्वारा जाराम करेंसी को लेकर महिला ने स्पष्ट किसी तरह की जानकारी नहीं दी,जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में ली गई महिला 40 वर्षीय सरिता यादव पारी मनोज यादव है, जो उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर जिला के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के पालिया जयसिंहपुर की रहने वाली है। आवश्यक कार्यवाही के बाद एसएसबी ने जप्त नेपाली करेंसी के साथ महिला को फारबिसगंज कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया।

अवैध हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार

AGENCY KATI HAR : जिले के कोढ़ा थाना पुलिस ने अपराधी की योजना बनाते हुए हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर अहिमालक गांव की ओर भूम रहा है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष अपने बल के साथ अहिमालक गांव पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़ा व्यक्ति की पहचान सतीश कुमार सिंह (32वर्ष) पिता अर्जुन सिंह के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी ग्राम खैरिया वार्ड नं.-04, थाना कोढ़ा जिला कटिहार का निवासी है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा बरामद कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

ब्रह्मपुर के बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में निर्माण पर डीएम नाराज

AGENCY BUXAR : जिले के ब्रह्मपुर स्थित बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर परिसर में विकास के नाम पर धार्मिक मयार्दा के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्य का मामला शनिवार को जिलाधिकारी साहिता के निरीक्षण के बाद सामने आया। जिलाधिकारी मंदिर पहुंचकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का दर्शन-पूजन किया और फूलों के साथ बरिपर के प्रथम व द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धार्मिक परंपरा के अनुरूप न होने वाले निर्माण और छंटिया गुणवत्ता को देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। मंदिर से जुड़े लोगों ने अतिथि गृह के नाम पर धर्मशाला को तोड़ने, पुष्प वाटिका के अतिक्रमण, देवस्वरूप पूजनीय रुद्राक्ष और आवला वृक्ष के पास शीशालव की टंकी बनाए जाने की शिकायत की। नाराजन जी पांडे ने बताया कि इस संबंध में हाईकोर्ट में मामला भी दायर किया गया है। इस पर अनुमंडल अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि कोर्ट का निर्णय ही मान्य होगा। अतिथि गृह के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने इसे होटल जैसी बनावट वाला बताते हुए आपत्ति जताई और कहा कि मंदिर परिसर का विकास आध्यात्मिक अनुभूति देने वाला होना चाहिए। छंटिया दबावजे, रिड्रिकिया और रेलिंग देखकर अधिकारी निरुत्तर रह गए। जिलाधिकारी ने निर्माण एजेंसी को फटकार लगाते हुए तत्काल सुधार और बेहतर गुणवत्ता से काम कराने का निर्देश दिया। इस दौरान प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

अच्छी पहल सांसद पप्पू यादव ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव से की मुलाकात पूर्णिया को हवाई संपर्क का नया केंद्र बनाने का हो रहा प्रयास

AGENCY PURNIA : पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र को हवाई संपर्क के क्षेत्र में एक मजबूत और स्थायी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। दिल्ली में उन्होंने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा से मुलाकात कर पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ी विमान सेवाओं के विस्तार को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। सांसद पप्पू यादव ने ज्ञापन में पूर्णिया-पटना और पूर्णिया-रांची मार्ग पर एटीआर श्रेणी के विमानों का नियमित संचालन शीघ्र शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूर्णिया बिहार का सीमावर्ती और

इन मार्गों पर विमान सेवाओं की मांग

उन्होंने जिन प्रमुख मार्गों पर नियमित विमान सेवाओं की आवश्यकता बताई, उनमें पूर्णिया-गुवाहाटी-दिल्ली, पूर्णिया-पटना-दिल्ली, पूर्णिया-पटना-इंदौरबाद, पटना-पूर्णिया-गुवाहाटी, बैंगलूर-पूर्णिया और मुंबई-पूर्णिया शामिल हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इन रूट्स पर अकासा एयरलाइंस, एयर एशिया और इंडिगो जैसी प्रमुख एयरलाइंस को नियमित रूप से परिचालित किया जाए। दिल्ली-पूर्णिया-बागडोगरा और बागडोगरा-पूर्णिया-दिल्ली मार्ग पर नियमित विमान सेवा शुरू करने की लंबे समय से वली आ रही जन मांग का भी उल्लेख किया और वर्तमान में संचालित विमान सेवाओं को बिना किसी व्यवधान के जारी रखने का आग्रह किया।

रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है, जहां हाल में शुरू हुई विमान सेवाओं से क्षेत्र की जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिला रहा है। इससे आवागमन सुगम हुआ है और व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा

प्रशासनिक गतिविधियों को भी गति मिली है। उन्होंने बताया कि पूर्णिया की भौगोलिक स्थिति, यात्रियों की बढ़ती संख्या और सीमांचल-कोसी क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए पटना और रांची जैसी नजदीकी

राजधानियों से सीधी हवाई कनेक्टिविटी अब समय की मांग बन चुकी है। इन मार्गों पर एटीआर विमानों का संचालन शुरू होने से उत्तर-पूर्व बिहार, सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लाखों लोगों को

सीधा लाभ मिलेगा। सांसद ने यह भी आग्रह किया कि प्रस्तावित पूर्णिया-पटना और पूर्णिया-रांची एटीआर सेवाओं को भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत शामिल किया जाए, ताकि हवाई किराया किफायती रहे और आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा सुलभ बन सके। इसके साथ ही उन्होंने पूर्णिया-बागडोगरा-गुवाहाटी मार्ग पर भी एटीआर विमान सेवाओं की आवश्यकता बताई। उनका कहना था कि यह रूट बिहार, उत्तर बंगाल, सिक्किम और उत्तर-पूर्व भारत को जोड़ने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे पर्यटन, व्यापार और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।

भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद भी भारत से निर्यात 19 प्रतिशत बढ़े हैं



की गई है। इसी प्रकार, वियतनाम को किए गए निर्यात में 36 प्रतिशत, हांगकांग को 35.5 प्रतिशत, बेलजीम को 30.9 प्रतिशत, जर्मनी को 24.9 प्रतिशत, ब्राजील को 21.3 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया को 19 प्रतिशत, ब्रिटेन को 15.4 प्रतिशत, यूनाइटेड अरब अमीरात को 13.2 प्रतिशत, इटली को 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। और तो और, चीन को भारत से विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में भी 90.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। कुछ देशों को भारत से विभिन्न वस्तुओं के निर्यात केवल नवम्बर 2025 माह में ही नहीं बढ़े हैं बल्कि अप्रैल 2025 माह से नवम्बर 2025 माह की 8 माह की अवधि के दौरान भी तेज गति से बढ़े हैं। इस सूची में शामिल देश हैं - स्पेन - 54.5 प्रतिशत, चीन - 32.9 प्रतिशत, हांगकांग - 22.4 प्रतिशत, वियतनाम - 14.7 प्रतिशत, अमेरिका - 11.4 प्रतिशत, जर्मनी - 9.3 प्रतिशत, यूनाइटेड अरब अमीरात - 6.7 प्रतिशत, ब्राजील - 5.1 प्रतिशत एवं बेलजीम - 5 प्रतिशत। जबकि, भारत के इस अवधि में कुल निर्यात केवल 2.6 प्रतिशत से बढ़े है। अब यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत की ओर अपना रुख करती हुई दिखाई दे रही हैं। जर्मनी, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिसके सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.9 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है एवं जिसकी जनसंख्या 8.4 करोड़ है, भारत में अपने निवेश को दुगुना करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है। जर्मनी की विशाल बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जिमें सैमेस, वोक्सवागन, वोश एवं बीएमडब्ल्यू जैसी कम्पनियां शामिल हैं, अपनी विनिर्माणा इकाईयों की भारत में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, क्लीन इनर्जी, आर्टीफिशियल इंटेलिजेन्स, ग्रीन इनर्जी हाईड्रोजन एवं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों के साथ अपने

सहयोग को बढ़ा रही हैं। विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान, जिसका सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.29 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है एवं जिसकी जनसंख्या 12.3 करोड़ है, एवं जो तकनीकी रूप से विश्व के कुछ मुख्य उन्नत देशों में शामिल है, भी भारत को अपने कूटनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है एवं जापान ने आज भारत की ओर अपना रुख कर लिया है। चीन के साथ जापान के सम्बंध भी बहुत अच्छे नहीं है एवं हाल ही के समय में इन दोनों देशों के बीच राजनैतिक सम्बन्धों में कुछ खटास पैदा हुई है। इसलिए भी जापान, भारत को अपना रणनैतिक साझेदार एवं हितैषी के रूप में देख रहा है। भारत में अहमदाबाद एवं मुंबई के बीच विकसित का जा रही बुलेट ट्रेन भी जापान के सक्रिय सहयोग से ही सम्भव हो पा रही है। इसके लिए जापान ने बहुत ही सस्ती दरों पर जापानी मुद्रा, येन, में भारत को ऋण उपलब्ध कराया है। जापान की अति विशाल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों - टोयोटा एवं सोनी, आदि द्वारा भारत में अरबों डॉलर का निवेश किया गया है एवं ये कम्पनियां अपने निवेश को भारत में और आगे बढ़ा रही हैं। विश्व की सबसे बड़ी छठी अर्थव्यवस्था यूनाइटेड किंगडम, जिसके सकल घरेलू उत्पाद का आकार 3.73 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर हैं एवं जिसकी जनसंख्या 6.9 करोड़ है तथा जिसने भारत के साथ हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता सम्पन्न किया है, ने भी अब भारत की ओर अपना रुख कर लिया है। यूनाइटेड किंगडम, भारत के कुशल एवं प्रशिक्षित युवाओं का वीजा देकर अपने देश में आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है ताकि उसकी डबली अर्थव्यवस्था को किनारे पर लाया जा सके। हालाँकि, यूनाइटेड किंगडम के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत से रेडीमेड गारमेंट्स, जैम्स एवं ज्वेलरी, समुद्री

उत्पाद, कृषि उत्पाद आदि का ब्रिटेन को निर्यात तेज गति से आगे बढ़ने की प्रबल सम्भावना व्यक्त की जा रही है। भारतीय कम्पनियों द्वारा भी यूनाइटेड किंगडम में अपना निवेश बढ़ाया जा रहा है एवं हाल ही के समय में कई भारतीय कम्पनियों ने ब्रिटेन की कम्पनियों का अधिग्रहण कर लिया है। दक्षिण कोरिया, 1.95 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था एवं 5.2 करोड़ की जनसंख्या वाला देश भी अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ अपने व्यापारिक हितों को बढ़ा रहा है। दक्षिण कोरिया की सैमसंग, एलजी, हुंडाई, जैसी प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में अपनी उत्पादन इकाईयों की स्थापना की है एवं यह कम्पनियां भारत में स्थापित अपनी उत्पादन इकाईयों को विस्तार देने का प्रयास कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट फोन जैसे उपभोक्ता उत्पादों के बाजार पर दक्षिण कोरियाई कम्पनियों का दबदबा भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विश्व की सबसे बड़ी सांतवी अर्थव्यवस्था फ्रान्स, जिसके सकल घरेलू उत्पाद का आकार 3.28 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है एवं जिसकी जनसंख्या 6.6 करोड़ है, भी भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में एवं क्लीन इनर्जी के क्षेत्र में, यूरोप के बाहर अपना रणनीतिक साझेदार मानता है। सुरक्षा के क्षेत्र में तो फ्रान्स ने राफेल लड़ाकू विमान उपलब्ध कराकर भारत के हाथ मजबूत ही किए हैं। हाल ही के समय में ट्रम्प प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों से अमेरिका में होने वाले आयात पर लगाए गए टैरिफ से फ्रान्स सबसे अधिक नाराज देशों में शामिल है। फ्रान्स भारत के साथ ग्रीन तकनीकी, ग्रीन पावर, सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को और अधिक मजबूत करना चाहता है। उक्त वर्णित देशों के साथ ही, रूस के साथ भारत के सम्बंध पूर्व से ही बहुत मजबूत बने हुए हैं। रूस ने भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में सस्ती दरों पर कच्चा तेल उपलब्ध कराकर भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भारी मदद की है। दरअसल, रूस के साथ भारत के लगातार प्रगाढ़ हो रहे संबंधों के चलते ही अमेरिका ने भारत पर टैरिफ की दर को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। अमेरिका चाहता है कि भारत, रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदे। वैश्विक स्तर पर तेजी से परिवर्तित हो रहे घटनाक्रम में अब चीन भी भारत के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने एवं मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रहा है। विदेशी व्यापार के मामले में अमेरिका के बाद चीन ही भारत का सबसे बड़ा भागीदार है। कुल मिलाकर, विश्व के कई विकसित देश आज भारत के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत करना चाहते हैं ताकि भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार में वे अपनी पैठ बना सकें एवं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। इससे, निश्चित ही भारत के आर्थिक हित भी सधते हुए नजर आ रहे हैं।



प्रहलाद सबनानी

भारत सरकार की उक्त रणनीति का असर नवम्बर 2025 माह के भारत से विभिन्न वस्तुओं के निर्यात सम्बंधी जारी किए गए आंकड़ों में स्पष्ट रूप से देखने में आ रहा है। नवम्बर 2025 माह में भारत के निर्यात में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, अगस्त 2025 माह में ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत के उत्पादों पर अमेरिका में लगाए गए टैरिफ का कुछ असर अगस्त 2025 माह में ही होना दिखाई देने लगा था। जुलाई 2025 माह में भारत से विभिन्न उत्पादों का निर्यात 13.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा था और अमेरिका को विभिन्न वस्तुओं का निर्यात 27.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा था, जबकि अगस्त में यह वृद्धि दर गिरकर क्रमशः 5.8 प्रतिशत एवं 6.7 प्रतिशत तक नीचे आ गई थी।

संपादकीय

आखें तरेरता बांग्लादेश

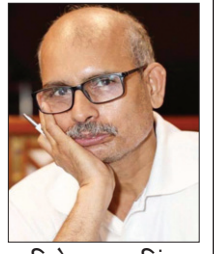
अपने विदेश दौरों की गिनती बढ़वा कर और सबसे अधिक देशों से वहां का सर्वोच्च सम्मान हासिल करने का रिकार्ड अपने नाम करवाने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगे हुए हैं। उनके लिए शायद बड़ी उपलब्धि यही होगी कि कितने राष्ट्रध्यक्षों को उन्होंने झुप्पी दी है, कितनों के साथ कार में अकेले सवारी की है और कितनों को पहले नाम से बुलाते हैं। लेकिन मोदी से पहले राष्ट्रध्यक्षों की विदेश नीति की धमक इस कारण से बनी हुई थी कि वह गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता था, वैश्विक शक्तियों के सामने नवीदित देशों को सम्मान के साथ खड़े होने का आदर्श उसने पेश किया और तीसरी दुनिया के देश भारत को बड़े भाई की तरह देखते थे। पाकिस्तान के साथ तो भारत के रिश्ते हमेशा नरम-गरम रहे, लेकिन पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश, पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार सब पर भारत का रसूख बना हुआ था, जो अब लगभग खत्म हो चुका है। इन सब देशों के साथ संबंध अभी सामान्य हैं, लेकिन जो गमाईट पहले हुआ करती थी, वो मोदी सरकार के आने के बाद खत्म हो गई है। खास तौर पर बांग्लादेश के साथ तो हमेशा से एक अपनापा रहा है। वहां का मुक्ति संग्राम भारत के कारण सफल हुआ। दोनों देशों का राष्ट्रगान रबीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, इस बात पर भी नागरिकों की खुशी होती थी। दोनों देश देख पाकिस्तान की सैन्य तानाशाही के नुकसान देख चुके हैं। इसके अलावा अविभाजित भारत का हिस्सा होने के कारण सांस्कृतिक, भाषायी, धार्मिक इतिहास की साझेदारी भी रही है। लेकिन अब वही बांग्लादेश भारत को न केवल तोड़ने की धमकी दे रहा है, बल्कि खुलकर पाकिस्तान और चीन के साथ जाते हुए भारत के योगदान की अवहेलना भी कर रहा है। बुधवार को भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमिदुल्लाह को तलब कर ढाका में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताई थी। इसी पर बांग्लादेश की नेशनल सितिजन पार्टी (एनसीपी) के सदरन चीफ ऑर्गनाइजर हसनत अब्दुल्लाह ने कहा कि भारत के उच्चायुक्त को देश से बाहर निकाल देना चाहिए था। इससे पहले अब्दुल्लाह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की धमकी दे चुके हैं। बता दें कि दो महीने में यानी फरवरी 2026 में बांग्लादेश में आम चुनाव होंगे और एनसीपी ने हसनत अब्दुल्लाह को कुमिल्ला-4 से उम्मीदवार बनाया है। इसी कुमिल्ला में अब्दुल्लाह ने भारत विरोधी बातें कहीं, उन्होंने कहा कि भारत के उच्चायुक्त को देश से बाहर निकाल देना चाहिए था क्योंकि वह शेख हसीना को शरण दे रहा है। हम आपका सम्मान करें और आप देखते ही गोली मारने की बात करो, ये सही नहीं है।

चिंतन-मनन



दिलीप कुमार पाठक

शीतकालीन संक्रांति वह दिन है जो मध्य शीतकाल का प्रतीक है और वर्ष के किसी भी अन्य दिन की तुलना में सबसे कम दिन के उजाले वाला दिन होता है। यह तब होता है जब दक्षिणी या उत्तरी ध्रुव सूर्य से अधिकतम दूरी पर होते हैं। इसका अर्थ है कि सूर्य वर्ष के किसी भी अन्य समय की तुलना



विनोद कुमार सिंह

मास्तीय लोकतंत्र में कुछ कानून केवल विधायी दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वे सामाजिक अनुबंध का रूप ले लेते हैं।महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,यानी मनरेगा,ऐसा ही एक कानून था।वर्ष 2005 में पारित इस अधिनियम ने पहली बार ग्रामीण भारत के नागरिकों को काम का कानूनी अधिकार दिया। अब,ठीक बीस वर्ष बाद, लोकसभा में भारी विरोध,हंगामे और विपक्षी प्रदर्शन के बीच 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)'संक्षेप में 'वीबी-जी राम जी' विधेयक संसद से पारित हो चुका है। संसद के शीतकालीन सत्र में सता पक्ष व विपक्ष ना केवल नोक - झोक चली बल्कि लोकतंत्र मॉडरि एक बार रणक्षेत्र में बदल गया। संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में जनता के हितो पर राष्ट्र निर्माण व विकास के मुद्दे पर बहस होनी थी,वहां मोदी सरकार अपने कई विधेयक संसोधन बिल को विपक्ष को दर किनार कर शोर गुल में पास किया है। इन विधेयक में मनरेगा बिल में संशोधन फिर इसे अधिकार से मिशन में स्थानांतरित किया गया है। जिस मनरेगा से 'वीबी-जी राम जी' और 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)'संक्षेप में 'वीबी-जी राम जी' विधेयक संसद से पारित हो चुका है। केन्द्र की सरकार इसे सुधार और विस्तार बता रही है,जबकि विपक्ष और

नेचर का रिसेट बटन: जब कुदरत लेती है नई करवट

में देर से उगता है और जल्दी अस्त होता है, सरल शब्दों में कहें तो सबसे लम्बी रात एवं सबसे छोटा दिन यह एक प्रमुख खगोलीय घटना है। पृथ्वी के ध्रुवों की ध्रुवीयता के कारण, उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति तब होती है जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है, और इसके विपरीत भी होता है। ग्रीष्मकालीन संक्रांति वह दिन होता है जिसमें सबसे अधिक दिन का प्रकाश होता है और सूर्य अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होता है, ऐतिहासिक रूप से, यह माना जाता था कि शीतकालीन संक्रांति सर्दियों के ठीक मध्य का प्रतीक है। हालाँकि, समय के साथ, अब कई लोग इसे सर्दियों की शुरुआत मानते हैं। मौसम विज्ञानी अमतौर पर संक्रांति से 3 सप्ताह पहले से ही सर्दियों की शुरुआत मानते हैं। 2026 में, उत्तरी गोलार्ध के देशों के लिए शीतकालीन संक्रांति आज 21 दिसंबर को होगी, जो दक्षिणी गोलार्ध में होने वाली ग्रीष्मकालीन

संक्रांति के साथ मेल खाएगी। मानव इतिहास में, शीतकालीन संक्रांति को एक महत्वपूर्ण अवसर माना गया है, जिसे इसके प्रतीकात्मक महत्व के कारण मनाया और पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया है। कई समाजों ने इस घटना को आध्यात्मिकता और आस्था से जोड़ा है, जबकि वैज्ञानिकता की दृष्टि से ये एक बड़ी घटना है। यह इंग्लैंड के स्टोनेहेंज स्मारक में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह लगभग 3000 ईसा पूर्व से अस्तित्व में है। इसके मुख्य पत्थर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दौरान सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और आस्था से जोड़ा है, और इसी से यह मान्यता बनी है कि प्रागैतिहासिक काल से ही लोग शीतकालीन संक्रांति की घटना को महत्व देते थे। इसका प्रमाण आयरलैंड गणराज्य में स्थित न्यूग्रेंज कब्रगाह है, जो 5,000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है और मिस्र के पिरामिडों और स्टोनेहेंज

से भी पुरानी है। शीतकालीन संक्रांति के दौरान, न्यूग्रेंज का कक्ष पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है, जो वर्ष में एक बार होने वाली एक अनोखी घटना को दर्शाता है। वहीं, भारत में शीतकालीन संक्रांति, मकर संक्रांति नामक एक पवित्र हिंदू त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। चीन में, इसे 24 सौर अवधियों में से 22वीं अवधि माना जाता है और आज भी इसे डोंगजे त्योहार के साथ मनाया जाता है, जिसमें परिवार एक साथ मिलते हैं और साल की सबसे लंबी रात एक साथ बिताते हैं। ये प्रकृति अपने आप में बहुत विशाल एवं दिव्यरूप है, आज के दिन एक रोचक मगर सत्यापित आश्चर्य होता है शीतकालीन संक्रांति के दिन, अगर आप दोपहर में बाहर खड़े होकर अपनी परछाई देखें, तो वह पूरे साल में आपकी सबसे लंबी परछाई होगी। इसका कारण भी प्रमुख है, हर दिन, सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, आकाश में एक चाप बनाता है।

मनरेगा से 'वीबी-जी राम जी'

नागरिक समाज इसे अधिकारों के क्षरण के रूप में देख रहे हैं।इस बहस को समझने के लिए प्रभावनाओं से अधिक जानकारी है— डाट,विलेपण व भावना। मनरेगा लागू होने के बाद से लेकर अब तक,यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार,पिछले दो दशकों में मनरेगा के तहत हर वर्ष औसतन 5 से 6 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला।सन 2013-14 से 2022-23 के बीच,हर साल औसतन 250 से 300 करोड़ मानव-दिवस का सुजन हुआ। कोविड-19 महामारी के दौरान,वर्ष 2020-21 में यह आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा,जब लगभग 389 करोड़ मानव-दिवस का सुजन हुआ और करीब 7.6 करोड़ परिवारों ने इस योजना के तहत काम पाया।यह केवल एक संख्या नहीं थी,बल्कि उस समय करोड़ों परिवारों के लिए जीवनरेखा थी,जब शहरों से लौटे प्रवासी मजदूरों के पास कोई विकल्प नहीं था। मनरेगा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यह योजना नहीं, बल्कि काम था।यदि किसी ग्रामीण परिवार को 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता था,तो राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था।नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की विभिन्न रिपोर्टों में यह स्पष्ट किया गया है कि इस कानूनी बाध्यता के कारण ही राज्यों और केंद्र पर काम उपलब्ध कराने का दबाव बना रहा।वही वजह थी कि 2006 से 2023 के बीच मनरेगा पर केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर लगभग 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए।केवल 2023-24 के बजट में ही मनरेगा के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।अब सरकार जिस नए कानून को लाई है,वह इस अधिकार-आधारित ढांचे को मिशन आधारित स्वरूप में बदल देता है।'वीबी-जी राम जी' विधेयक में यह दावा किया गया है कि ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन तक रोजगार मिलेगा,जो मनरेगा के 100 दिन की तुलना में अधिक है।लेकिन यहां सवाल संख्या का नहीं, गारंटी का है।मनरेगा में 100 दिन का रोजगार कानूनी अधिकार था,जबकि नए कानून में 125 दिन प्रशासनिक विवेक पर निर्भर होंगे।अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जब रोजगार की गारंटी कानून से हटकर मिशन बन जाती है,तो उसका क्रियान्वयन बजट, प्राथमिकता और राजनीतिक इच्छा पर निर्भर हो जाता है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार,नए विधेयक में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह यह तय करे कि कितने क्षेत्रों में काम होगा, किस तरह के काम

होंगे और किन परिस्थितियों में योजना को अस्थायी रूप से रोक जा सकता है।इसमें साल में दो महीने तक काम रोकें जाने का प्रावधान भी शामिल है। मनरेगा के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।वर्ष 2018 से 2022 के बीच,मनरेगा के तहत काम की मांग और उपलब्धता के आंकड़ों से स्पष्ट है कि कई राज्यों में पहले ही मांग के मुकाबले काम कम मिला।उदाहरण के लिए, 2021-22 में लगभग 8 करोड़ परिवारों ने काम की मांग की, लेकिन औसतन केवल 52-55 दिन का ही काम उपलब्ध हो सका। आलोचकों का तर्क है कि जब मौजूदा व्यवस्था में ही 100 दिन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा था,तो बिना कानूनी बाध्यता के 125 दिन कैसे सुनिश्चित होंगे।मनरेगा का सामाजिक प्रभाव केवल रोजगार तक सीमित नहीं था।सरकारी आंकड़ों के अनुसार,मनरेगा के तहत काम करने वालों में लगभग 56 प्रतिशत महिलाएं थीं।वह भारत की सबसे बड़ी महिला-भागीदारी वाली योजना थी।इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भागीदारी क्रमशः लगभग 20 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रही।कई अध्ययनों में यह पाया गया कि मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरी दरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।भारतीय रिजर्व बैंक और विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोध बताते हैं कि जिन जिलों में मनरेगा का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ,वहां कृषि मजदूरी में 8 से 12 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई।नए 'वीबी-जी राम जी' कानून को लेकर आशंका यह जताई जा रही है कि लक्षित लाभार्थी मॉडल अपनाते से महिला, दलित और आदिवासी भागीदारी घट सकती है।मनरेगा में स्व-चयन का सिद्धांत था—जो भी काम चाहता था,उसे काम मिलता था। नए मिशन में लाभार्थियों का चयन प्रशासनिक मानदंडों पर आधारित होगा।सामाजिक संगठनों का कहना है कि इससे सबसे हाशिये पर खड़े लोग छूट सकते हैं। अर्थशास्त्रियों ने इसके व्यापक आर्थिक प्रभावों की ओर भी ध्यान दिलाया है।मनरेगा पर किया गया खर्च सीधे ग्रामीण मांग को बढ़ाता था। वर्ष 2020-21 में,जब मनरेगा पर खर्च बढ़ाया गया,तब ग्रामीण खपत में गिरावट अपेक्षाकृत कम रही।राष्ट्रीय नमूना सर्वे और उपभोक्ता व्यय के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि मनरेगा अपने ने खाद्य सुरक्षा और बुनियादी उपभोग को बनाए रखने में मदद की।जयंति घोष के अनुसार, यदि मनरेगा जैसे अधिकार-आधारित कानून को कमजोर किया जाता है,तो कुल मांग में गिरावट आएगी, जिसका असर उद्योग और सेवाओं तक पहुंचेगा।संसद के बाहर

विरोध केवल राजनीतिक नहीं,बल्कि वैचारिक भी है।दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यॉं देजन ने कहा कि मनरेगा 'जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाया गया कानून' था। उन्होंने याद दिलाया कि 2005 से पहले ग्रामीण भारत में रोजगार गारंटी को कोई अवधारणा नहीं थी। आज यह कानून न केवल भारत, बल्कि वैश्विक सामाजिक नीति के क्षेत्र में एक संदर्भ बिंदु बन चुका है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की कई रिपोर्टों में मनरेगा को सामाजिक सुरक्षा का अभिनव मॉडल बताया गया है।विपक्षी दलों का तर्क है कि नए कानून से संघीय ढांचे पर भी असर पड़ेगा।मनरेगा में ग्राम पंचायत की केंद्रीय भूमिका थी। कार्यों की योजना स्थानीय स्तर पर बनती थी।सरकारी आंकड़ों के अनुसार,मनरेगा के तहत 60 प्रतिशत से अधिक कार्य जल संरक्षण,सिंचाई और ग्रामीण परिसंपत्तियों से जुड़े थे,जिनका सीधा लाभ स्थानीय समुदाय को मिला।नए कानून में केंद्रीय नियंत्रण बढ़ने से स्थानीय जरूरतों की अनदेखी हो सकती है।चयन जालवा जा रहा है।मनरेगा संघर्ष मोर्चा और अन्य नागरिक संगठनों ने 19 दिसंबर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की है।उनका कहना है कि यह लड़ाई केवल एक योजना की नहीं,बल्कि सिंधधान के अधिकार के लिए करी है, जिसमें राज्य नागरिकों को अधिकार देता है,न कि दवा। यदि आंकड़ों के आँदने में देखा जाए, तो स्पष्ट है कि मनरेगा केवल खर्च नहीं,बल्कि निवेश था।ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकलन के अनुसार,मनरेगा के तहत बने जल संरक्षण और सिंचाई ढांचे से कृषि उत्पादकता में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।कई राज्यों में सूखे की तीव्रता कम करने में इस योजना की अहम भूमिका रही।नए कानून में इस तरह के दीर्घकालिक परिसंपत्ति निर्माण पर कितना जोर होगा,यह अभी स्पष्ट नहीं है। अंततः सवाल यही है कि भारत किस दिशा में जाना चाहता है।क्या वह अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा,या उसे मिशन और लक्ष्य आधारित योजनाओं में बदल देगा।'वीबी-जी राम जी' विधेयक का पारित होना इस बहस का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है।आने वाले समय में इसका वास्तविक प्रभाव और नतीजा में दिखाई देगा—कितने परिवारों को काम मिला,कितने दिन मिला,और किस कीमत पर।लेकिन फिलहाल, मनरेगा से 'वीबी-जी राम जी' तक की यह यात्रा ग्रामीण भारत के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लाती देती है।

A beacon on the shore of a stormy sea

The New Yorker, one of the anglophone world’s most respected weekly news magazines, died the same year it was born in 1925. However, it was resurrected the same day before the world could even realise that it was briefly dead. Despite the uncertainty of its early months and years, the magazine has survived, and now celebrates its centenary year of existence.

James Thurber in his classic 1957 memoir, The Years With Ross, on Harold Wallace Ross, the founder-editor of The New Yorker, wrote with characteristic humour that the magazine was an “outstanding flop of 1925” when there was so much of success around in literature, music, and entertainment: “Its continued existence may be accurately called life after death... the weekly was declared dead at an executive luncheon in New York, presided over by its chief backer, Raoul Fleischmann. Then a miracle, in the form of a chance encounter, resurrected the deceased. Several hours after the coroner’s verdict, Ross ran into Fleischmann at the wedding of Franklin Pierce Adams, and, in that atmosphere of hope, beginning, and champagne, they decided to have another go at it.”In what seems to have come a full circle, the magazine celebrates its 100 years at a time when all the talk is about the demise of the print media, especially the magazine format. The New Yorker itself has spread its wings and vision in recent years to become a multimedia brand. The magazine did not merely survive in the city of its making, but over the decades became a gentle obsession of a distinct class of readers across the globe. For a magazine that saw so much of history unfold, from world wars to cold wars to culture wars, the refinement of reason it cultivated was miles away from being an ideological smithy. It did not impatiently try to proselytise anybody or propel a social and political movement, but was still a movement that gently, humanely, shaped the worldview of its readers. It’s never easy for old institutions to weather transformation; but The New Yorker, in its present avatar, does not look wrinkled with crumbling knees. It is among the news brands that has successfully learnt to carry the weight of its own history, even while being constantly reminded by its own readers and writers as to what it really is, and what it should always be.

To wade past the departments of nostalgia, to keep old loyalties, and cultivate new ones simultaneously is the trickiest part of the business. To ensure that one is not read by habit alone, but for quality, and to manage disruptions in the editorial mix is a stupendous challenge. A recent Netflix documentary on the magazine directed by Marshall Curry captures these transitions rather skillfully. The documentary is just one slice of the understated celebrations at The New Yorker’s skyscraping landmark.

Since we live in an age of fake news and post-truth assertions, it is significant to note that right from its beginning, The New Yorker was obsessed about the idea of fact-checking. As technology progressed, the magazine perhaps borrowed a method from science to make its prose not just incisive, but verifiably precise. It established a protocol around opinion very early. Thurber wrote: “[Ross’s] checking department became famous in the trade for a precision that sometimes leaned over backward. A checker once said to me, ‘If you mention the Empire State Building in a Talk piece, Ross isn’t satisfied it’s still there until we call up and verify.’” This fact-checking culture became more established with Ross’s successor William Shawn, then the two editors who followed him, Robert Gottlieb and Tina Brown. The magazine has continued to answer the complexity of the question under its current editor, David Remnick. In the Netflix documentary, an Indian woman with a nose pin is seen verifying cat names.

Something is rotten in the state of Goa

Arpora nightclub blaze has exposed blatant violations and rampant corruption

GOA, a tiny state on the western coast of India, is the land of my ancestors, who were Hindus. My maternal grandmother told me that our distant ancestors had arrived there with the sage Parshuram, who had fired an arrow that struck the fertile land of Goa, following which the Goud Saraswat community has been living there for aeons.The last time I met my grandmother was in 1952, when I arrived at her home unannounced with my books to prepare for the UPSC’s civil services examination. She stayed alone in her huge house with an old woman for company and to cook her meals. I arrived after dusk. To my surprise, all the doors were open. Murders and thefts were rare in Goa in those times.

Goa has progressed into a state comparable to any other in the Indian Union, alive in a sense that it is afflicted by crime and corruption. When the colonial rulers, the Portuguese, were driven out in 1961, the state was merged into the Union of India. The two core services, the IAS and the IPS, were introduced and the judiciary reorganised on the lines of neighbouring states.At first, the local inhabitants were very happy. The new rulers were among their own and till the casino culture gained prominence in Goa, disaffection with those who ruled was minimal. The Congress gave way to the BJP, which ensnared most of the rival legislators through the lure of office.It can be safely said that till BJP leader Manohar Parrikar was the Chief Minister, crime and corruption had been checked despite the influx of citizens from northern states and the inroads of the casino culture.

The current government led by Pramod Sawant has allowed the hold that Parrikar had on the administration to slip so badly that Herculean efforts will be needed to restore the rule of law. The fire that swept through the nightclub called Birch by Romeo Lane, killing 25 people — including 20 poor migrants who had shifted to Goa to make a living — sums up the sorry state of governance under Sawant’s rule.Two brothers, Gaurav and Saurabh Luthra, owned the nightclub, along with “sleeping partner” Ajay Gupta. The land had been leased to them by the owner, Surinder Kumar Khosla, though he knew that no construction was permitted there since it lay astride former salt pans.It has been reported that Gaurav and Saurabh, both residents of Delhi, share their residential address with 42 firms, most of which are probably shell companies. The Enforcement Directorate would be well advised to ascertain if these firms are conduits for money



roofs — all combustible material. They were informed telephonically within minutes of the disaster. Immediately, they booked a flight to Thailand to avoid arrest. CM Sawant’s minions went into top gear and managed to get the brothers arrested from Phuket. The government hoped that the public would forget that the real culprits were those who had shut their eyes to the illegalities.Who are the officials who permitted the nightclub to operate brazenly on land on which no construction was permitted? If a politician has given the green signal, he or she should be exposed. Why have the erring officials not been named as co-accused along with the Luthra brothers and the landowner?

The officer in charge of the police station where the nightclub was operating is reported to have sent a written

report to his superiors. He alleged that he was told to “keep quiet”. If that is so, there is no solace for law-abiding citizens of Goa if the senior officers who should have enforced the law are themselves complicit in the crime committed under their very noses.

My brother retired as the head of the Town and Country Planning Department in the Central government. He worked for five years after retirement as the Director of the School of Planning and Architecture in New Delhi. He told me that he is not abreast of the happenings in his previous department in Goa, though he lives in our ancestral home in the village. I consulted him about this fiasco. His first comment was that the land on which the nightclub was built was an “eco-sensitive zone, subject to tidal action”. According to the Goa Regional Plan (2001-21), which was approved in 2008, no construction can be permitted on such land.

The second mandatory requirement that was disregarded was that there has to be a minimum distance of 70 metres between any building and the spot which a fire tender can access. In the Arpora case, the fire tenders had to operate from a distance of 400 metres, which was obviously ineffective. Planners should have pointed out these requirements to those empowered to permit construction.Most native Goans feel that there is no governance in their state. It has collapsed beyond repair and only a change of guard can stem the rot.

The CM is attempting to shift the blame to officials. He has suspended a few of them and threatened not to spare any other who has not acted in good faith. He has not pointed a finger at any politician! But without political blessings, these violations could not have occurred. Goa is too small a state for its residents not to be aware of the levels to which corruption has risen.

The 20 migrants who lost their lives represented the India that has not benefited from PM Narendra Modi’s development initiatives and the economic advances the country has made. There appears to be a sense of oblivion about the existence of this India when decisions have to be taken, like they have to be taken every day by those who rule.When Covid struck, our Prime Minister abruptly announced a lockdown. He forgot to factor in the poor migrants who were left without shelter and sustenance. PM Modi’s acolytes in Goa apparently don’t spare a thought for the migrants who go there to make a living. Forgetting about this parallel, poor India is inexcusable.

Bengaluru must sustain recent cleanliness gains

The country’s IT capital seems to be finally sloughing off its embarrassing title of ‘Garbage City’ with a multi-pronged strategy



The country’s IT capital seems to be finally sloughing off its embarrassing title of ‘Garbage City’ with a multi-pronged strategy. The recent changes in Bengaluru are not the government’s doing alone—it includes residents segregating waste at source more scrupulously and paying a waste management cess. For itself, the city administration is clearing dirty spots, its marshals are hounding litterbugs, and an extensive campaign against single-use plastic is on. An integrated waste management system has been implemented to scientifically dispose of e-waste, channel plastic into road-building and cement-manufacturing, and produce energy from waste. Helplines and 76 Kasa kiosks or centres for segregated waste have been set up. All of this adds up to a promising start that deserves to be sustained.This collaborative system is necessary for a city where roadside waste heaps have become the norm, landfills have risen in the suburbs, and the population has displayed increasing disdain for discipline. Deputy Chief Minister D K Shivakumar, who holds the Bengaluru development portfolio, has shown his resolve to bring in change. As the Greater Bengaluru Governance Act, 2024 came into force this May, the city

was divided into five zones for easier management. The garbage contractors’ cartel was dismantled, and a battery of senior officers brought in to oversee waste management. The ‘garbage tax’, which yielded ₹350 crore in two months, is being ploughed back into the city.The country’s IT capital seems to be finally sloughing off its embarrassing title of ‘Garbage City’ with a multi-pronged strategy. The recent changes in Bengaluru are not the government’s doing alone—it includes residents segregating waste at source more scrupulously and paying

a waste management cess. For itself, the city administration is clearing dirty spots, its marshals are hounding litterbugs, and an extensive campaign against single-use plastic is on. An integrated waste management system has been implemented to scientifically dispose of e-waste, channel plastic into road-building and cement-manufacturing, and produce energy from waste. Helplines and 76 Kasa kiosks or centres for segregated waste have been set up. All of this adds up to a promising start that deserves to be sustained.This collaborative system is necessary for a city where roadside waste heaps have become the norm, landfills have risen in the suburbs, and the population has displayed increasing disdain for discipline. Deputy Chief Minister D K Shivakumar, who holds the Bengaluru development portfolio, has shown his resolve to bring in change. As the Greater Bengaluru Governance Act, 2024 came into force this May, the city was divided into five zones for easier management. The garbage contractors’ cartel was dismantled, and a battery of senior officers brought in to oversee waste management. The ‘garbage tax’, which yielded ₹350 crore in two months, is being ploughed back into the city.

Filling the Constitution’s eloquent gaps

Constitutions derive much of their power from what they leave unsaid. Indian courts have implicitly sided with legal philosopher Ronald Dworkin, for whom the law encompasses not merely explicit rules, but also principles. But when courts fill textual gaps, do they discover latent rights or create new laws

Ludwig Wittgenstein famously concluded his Tractatus Logico-Philosophicus with the injunction: “Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.” Yet, when it comes to constitutions, silence seldom restrains. It is often the very space into which the judiciary speaks.

The Indian Constitution, among others, derives much of its transformative power not from what it proclaims, but from what it leaves unsaid. This silence, far from being a void, has emerged as a crucible in which our most progressive jurisprudence has been forged. The concept of constitutional silence admits multiple taxonomies. There is intentional silence, where the framers deliberately leave matters open-ended, bequeathing interpretive flexibility to future generations. Then there is the unintentional silence, which arises from the inevitable lacunae left unforeseen that no Constituent Assembly, however prescient, could have anticipated. The distinction matters, as courts have historically treated deliberate omission with greater deference than inadvertent oversight.As Michael Foley observed in The Silence of Constitutions, certain gaps are valuable “not in spite of their obscurity, but because of it”. These constitutional abeyances provide the mechanism by which intractable conflicts are postponed until political conditions permit resolution. The basis on which courts address textual gaps reveal deeper commitments about the nature of law. Hans Kelsen’s positivism advanced the closure principle—where law does not explicitly prohibit, it implicitly permits. For Kelsen, apparent gaps merely represent interpretive ambiguities within a conceptually complete normative hierarchy crowned by the Grundnorm.H L A Hart’s riposte in The Concept of Law introduced the enduring concept of open texture. He

stated that legal rules possess a “core of settled meaning” surrounded by a “penumbra of debatable cases” where judges exercise strong discretion, effectively legislating rather than discovering pre-existing rights.

Ronald Dworkin challenged this discretion thesis fundamentally. His hypothetical judge Hercules, possessed of “superhuman intellectual power and patience”, could always identify the single right answer through principled interpretation to address a fundamental jurisprudential problem: How do judges resolve cases where established legal rules provide no clear answer? For Dworkin, law encompasses not merely explicit rules, but also principles. These principles are the background moral considerations providing answers even where rules are silent.

The debate crystallises a question central to constitutional silence: when courts fill gaps, do they discover latent rights or create new law? Indian jurisprudence has implicitly sided with Dworkin, treating unenumerated rights as embryonic within constitutional text rather than judicial innovations.The Supreme Court’s transformation of Article 21 exemplifies this approach with particular eloquence. The provision’s text is spare—“no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law”. Neither ‘life’ nor ‘personal liberty’ receives a definition. This silence has proved generative beyond measure. In the Maneka Gandhi (1978) case, the Supreme Court declared that



personal liberty possesses “the widest possible amplitude”. It displaced the earlier, restrictive interpretation adopted in AK Gopalan (1950).

From this foundation, courts have read into silence a

constellation of unenumerated rights: to livelihood, clean environment, speedy trial, free legal aid, education, health, and human dignity. Each represents not judicial legislation, but what Justice Chandrachud in Puttaswamy (2017) described as rights “inherent in every human being by birth”, a naturalist framing that treats constitutional silence as concealing rather than precluding. The court’s unanimous declaration of

privacy as a fundamental right, despite the Constituent Assembly’s express rejection of Fourth Amendment-style protections, demonstrates this.The basic structure doctrine represents perhaps the most consequential exercise in addressing constitutional silence. Article 368 was originally silent on limits to parliament’s amending power. In Kesavananda Bharati (1973), the court quoted German jurist Dieter Conrad: “Any amending body organised within the statutory scheme, howsoever verbally unlimited its power, cannot by its very structure change the fundamental pillars supporting its constitutional authority.” The doctrine exemplifies deriving implied limitations from constitutional architecture rather than explicit text. As Justice A K Ganguly observed in Bhanumati (2010): “The basic structure doctrine vis-à-vis Article 368 emerged out of this concept of silence in the Constitution.”The concept of constitutional morality, traced to English historian George Grote and emphasised by B R Ambedkar, also provides courts with the tool for filling silences. Justice D Y Chandrachud’s observation in the Delhi governance case of 2018 that “constitutional morality requires filling in constitutional silences to enhance and complete the spirit of the Constitution” articulates the idea that the silences be filled by constitutional morality than majoritarian sentiment.

Silver slips after hitting record high of Rs 2.04 lakh/kg in Delhi, gold flat

New Delhi.(Agency)

Silver prices retreated from the record level in the national capital on Friday, with the white metal plunging by Rs 3,500 to Rs 2,04,100 per kilogram due to emergence of fresh selling from stockists and retailers, according to the All India Sarafa Association.It had surged Rs 1,800 to scale a fresh peak of Rs 2,07,600 per kg on Thursday.

In the local bullion market, gold prices are traded almost flat at Rs 1,36,515 per 10 grams (inclusive of all taxes) from Thursday's closing of Rs 1,36,500 per 10 grams.In the international markets, spot gold slipped by USD 10.09, or 0.23 per cent, to USD 4,322.51 per ounce.On the other hand, spot silver was trading 0.56 per cent higher at USD 65.85 per ounce in the overseas trade.

Digital healthcare Company Practo planning IPO: What's the timeline



Kolkata.(Agency)

Practo is a digital-first healthcare platform that connects patients with healthcare providers such as hospitals and doctors via online booking and teleconsultations, pharmacy. The company employs a B2C and B2B model. The revenue streams are from subscription fees, commissions, advertising and corporate health packages. Practo is a 17-year-old company. Its investors include Sequoia Capital, Matrix Partners and Tencent Holdings.It allows patient parties to find doctors, clinics, hospitals with verified credentials does bookings for in-person appointments and/or online consultations/telemedicine. It also allows patients to order medicines and book lab tests and even store and manage personal health records. In their B2B segment Practo offers clinic management software for appointments, EMR, billing, and analytics.Practo is now preparing to come out with its public issue. Reports have stated that Practo is on the way of finalising merchant bankers to manage the public issue. Also a Bloomberg report has stated that Practo holding ompany is based in Singapore and it is preparing to shift its head office in India and it could be over in a couple of months.

Talks with potential lead managers

Practo is headquartered in Bangalore. It has now intensified discussions with potential advisors for the public issue. According to sources, bankers could be appointed by January. However, the IPO structure and exact timeline are yet to be finalised and obviously these could change. It is believed that this healthcare company may launch its IPO in the market by the second half of 2026.

Strong IPO market

The IPO deluge and the enthusiastic investor response to these issues have triggered the Practo management. There have been as many as 103 IPO listings in 2025 so far (till Dec 20) and some of the shares are doing very well. The increasing participation of retail investors and continuous inflows into mutual funds have boosted the confidence of companies trying to raise capital from the market. Almost a dozen and a half of startups have successfully tapped the capital markets this year. Practo's IPO plan is a sign that growth-stage and technology-based companies are feeling emboldened to mobilise capital in this market.

Did MGNREGA act as safety net for casual labour during sowing, harvest

New Delhi.(Agency)

One of the most contentious provisions of the new rural employment Bill — which seeks to replace the 20-year-old MGNREGA — is that it empowers the states to pause the scheme for 60 days of their choice during peak sowing and harvest seasons.

The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G) Bill, which was passed by the Parliament on Thursday drew flak from several quarters over this provision.

A section of civil society claimed that it will reduce the bargaining power of manual casual labour, as MGNREGA acted as a safety net and a fall-back option if farms did not give them a better deal in terms of wages. Data shows that typically, work demand for MGNREGA dipped from July to November in each financial year, coinciding with peak kharif and rabi sowing and harvest seasons across most parts of India. This was also the time when perhaps farms offered better wages to these workers during sowing or harvesting time, or MGNREGA wages were so low that they were not the first choice for workers and only acted as a safety net in times of crisis.With this safety net gone, civil society groups and activists say that it could open the labour market to exploitation.The government, however, said that the two-month pause in work will have to be aggregated and not continuous and will prevent labour shortages during critical farm operations and avoid labour being diverted away to guaranteed-wage worksites. This, in turn, would prevent wage inflation, as stopping public works during peaks prevents artificial wage inflation that raises food production costs. The argument also is that with machines being extensively used in farms nowadays across India, the use of manual labour for agriculture activities is going down with each passing day.Meanwhile, a group of eminent economists from across the world wrote an open letter to the Indian government in support of MGNREGA, saying that the current shift to devolve the scheme to states and without commensurate fiscal support, will threaten MGNREGA's existence.

Govt likely to miss income tax collection by a big margin

Net income tax collection in FY26 till December 17 rose by 6.4% to Rs 8.47 lakh crore against Rs 7.96 lakh crore even as the total net direct tax collection rose by 8%

New Delhi.(Agency)

The government is likely to miss its ambitious income tax collection target of 15% for FY26 by a big margin. Despite the 2025 Union Budget announcing a major relief to individual taxpayers, the government had set a steep target of 15% growth in income tax collection in FY26. However, going by the net income tax

collections till 17th December, the government might miss the target by a big margin.Net income tax collection in FY26 till December 17 rose by 6.4% to Rs 8.47 lakh crore against Rs 7.96 lakh crore even as the total net direct tax collection rose by 8%. To achieve the budget target Rs 14.4 lakh crore, the income tax collection must grow by 70% in the next three months.

“Overall, ICRA expects a sizeable miss in personal income tax collections relative to the FY26 Budget target of Rs. 14.4 lakh crore, which entails a 15% growth over the FY2025 provisional number,” says Aditi Nayar, Chief Economist, ICRA Ltd.Finance minister Nirmala Sitharaman in the Budget 2025 announced a slew of sops to ease the burden on the taxpayers of the country. Her personal income tax proposals include an increase in the threshold up to which no tax is levied on

income. The income threshold was increased from Rs 7 lakh to 12 lakh, making any income up to Rs 12.75 lakh tax free (after including the standard deduction of Rs 75,000).

The new tax slab also significantly reduces the tax burden on all with the highest tax rate of 30% applicable on income over Rs 24 lakh from the earlier Rs 18 lakh. The new tax slab also increases the basic

exemption limit from Rs 3 lakh to Rs 4 lakh, which means the first Rs 4 lakh would attract no taxes. The government had estimated a revenue loss of Rs 1 lakh crore due to its direct tax proposals in the Budget.Meanwhile, corporate income tax collection rose by 10.5% so far in FY26 till 17 December 2025 to Rs 8.17 lakh crore. The budget target for FY26 is Rs 10.82 lakh crore. Corporate advance tax collection during the period rose by 8%, while advance personal income tax collection declined 6.5% during the period.“Overall the corporate advance tax increase signals good corporate earnings. Non- corporate advance tax collections have however declined possibly on the back of rate cuts for individuals given in the previous budget,” says Rohinton Sidhwa, Partner, Deloitte India.



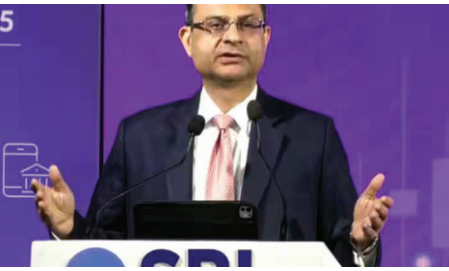
RBI's Central Board Deliberates On Domestic And Global Economic Situations

New Delhi.(Agency)

New Delhi: The Reserve Bank of India's (RBI) central board, on Friday, deliberated on the state of the local and international economies and related issues, with Governor Sanjay Malhotra presiding over the 620th meeting of the Central bank's central board of directors. According to a statemet from the RBI, the Board also approved the risk-based deposit insurance framework for banks. "The 620th meeting of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India was held today in Hyderabad under the Chairmanship of Governor Sanjay Malhotra," RBI said in an official statement.The Board discussed the global and domestic economic situation and associated challenges. Additionally, it examined the Trend and Progress of Banking in India, 2024-2025 draft report, and the operations of a few Central office departments."It approved the risk-based deposit insurance framework for banks. The Board also reviewed the activities of select Central Office

Departments and the draft report on Trend and Progress of Banking in India, 2024-25," the statement added.

The meeting was attended by Deputy Governors T. Rabi Sankar,



Swaminathan J, Poonam Gupta, and Shirish Chandra Murmu. Other directors of the Central board -- Nagaraju Maddirala, Department of Financial Services Secretary; Satish K Marathe, Revathy Iyer, Pankaj Ramanbhai Patel, and Ravindra H Dholakia, too, attended the meeting.

Earlier, the RBI had issued a compounding order under Section 15 of the Foreign Exchange Management Act

(FEMA), 1999, in the case of Nearbuy India Private Limited, which has resulted in the termination of proceedings against the company for alleged contraventions of the Act, the Enforcement Directorate (ED) said.

The order was passed by the RBI on October 17 after the issuance of "No Objection" by the ED, an agency statement said. In this case, based on credible information received, an investigation was taken up by the ED under the provisions of the Act.

"After completion of investigation, the agency filed a complaint under FEMA before the Adjudicating Authority on December 3, 2024, pointing out the contraventions under the FEMA which include late reporting of foreign inward payments under Para 9(1)(A) of Schedule 1 to FEMA 20/2000-RB, covering Rs 35.82 crore, late filing of Form FCGPR after issuing shares under Para 9(1)(B) of the same schedule, covering Rs 73.01 crore."

The RBI has now done the compounding for these contraventions, the statement said.

Adani Group in talks for nuclear sector entry through SMR project in UP



New Delhi.(Agency)

Gautam Adani's conglomerate is in discussions with the Uttar Pradesh government to foray into India's nuclear sector. According to a news report citing sources, the company plans to build eight 200-megawatt Small Modular Reactors (SMRs) within the state.However, the state government has yet to identify a suitable riverside site, which is essential to ensure a steady water supply for the reactors. Other major Indian conglomerates, including the Tata Group, Reliance Industries Ltd., and the JSW Group, are also jockeying for access to this emerging sector.

As per the report, the discussions with the Uttar Pradesh government are centered on a public-private partnership (PPP) model. Under this arrangement, the state-run Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL) would operate the proposed plant on behalf of the Adani Group.The state-run Bhabha Atomic Research Centre (BARC) is currently working on the design and development of the 200 MW SMRs that the Adani Group intends to install. The entire project is expected to take five to six years to complete following government approval. Sources noted that the timeline is slightly extended because the Adani Group is a new entrant in the nuclear energy space.

India currently operates approximately two dozen nuclear reactors across seven locations, contributing roughly 3% of the country's total electricity generation, according to a parliamentary statement made in July. While current capacity stands at 8,780 MW, plans are underway to boost this to 13,600 MW through projects in various stages of implementation.

Meanwhile, the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Bill, 2025, was introduced in the Lok Sabha on December 15, 2025, and has since been passed by both Houses of Parliament. The SHANTI Bill replaces the Atomic Energy Act, 1962, and the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010. While the 1962 Act previously governed the development of atomic energy.

India, Oman FTA to come into effect in 3 months

NEW DELHI.(Agency)

he India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) will come into effect within three months, the Commerce and Industry minister Piyush Goyal said on Friday, a day after the two countries signed the agreement. Goyal also said that several Indian companies like Apollo, Amul, Amity will be exploring investment opportunities in Oman, confirmed the minister.

“The Oman minister and I have discussed and decided that we will try to operationalise the agreement within three months,” said Goyal during a media briefing on Friday.

India will get duty-free market access for its 99% exports in value terms to Oman. Currently, only 15.33% of India's exports enters Oman at zero duty under the MFN regime.As highlighted by Commerce Secretary Rajesh Agrawal, one of the biggest gains from this FTA comes from the services sector, with Oman opening up

100% Foreign Direct Investment (FDI) for India. This move can boost India's services exports.

India is planning to invest in domains like battery manufacturing, green hydrogen



production, education and medical sector in Oman. Amity and Apollo Group have committed to make investments for the education and healthcare sectors, respectively.While Oman has opened the majority of the sectors for India, the latter has maintained a protectionist stance for

some of its sensitive sectors. As confirmed by the Ministry, India has placed 2,789 tariff lines in the exclusion list under the India-Oman CEPA, protecting key domestic sectors such as transport equipment, major chemicals, cereals, fruits and vegetables, spices, coffee and tea, and animal-origin products.Sensitive value-chain industries including rubber, leather, textiles, footwear, petroleum oils, and mineral-based products are also shielded to safeguard manufacturing competitiveness and farmer interests.While India has maintained its protectionist stance for the dairy sector, Amul India and Oman Dairy have planned to get into a joint venture to set up their plant in Oman.

“Already we have received an interest from the Oman dairy to have a joint venture with Amul dairy and other dairies in India are also welcome to go and explore the potential there,” said Goyal.

Indian Indices End Week In Bullish Tone Over Positive Global Cues

At close, the Sensex was up 447.55 points or 0.53 per cent at 84,929. Indian equities were traded in a cautious tone for most of the week, weighed down by persistent FII outflows, rupee depreciation, and heightened global uncertainties.

New Delhi.(Agency)

Indian equity benchmarks closed on a strong note this week, snapping a four-day losing streak amid positive global cues stemming from US inflation data. The market ended the week in a bullish tone



with Nifty surging 0.18 per cent during the week and 0.58 per cent on the last trading day to 25,966, after a softer US CPI print boosted expectations of a milder Fed stance.

At close, the Sensex was up 447.55 points or 0.53 per cent at 84,929. Indian equities were traded in a cautious tone for most of

the week, weighed down by persistent FII outflows, rupee depreciation, and heightened global uncertainties. Further, early sessions also saw pressure from rising Japanese bond yields and expectations of Bank of Japan (BoJ) tightening, which amplified risk-off sentiment across emerging

markets.Bargain hunting and lower crude prices helped large caps drive a late rebound, trimming most of the week's losses, market watchers said. Broader indices also rose marginally during the week, with the Nifty Midcap100 up 0.04 per cent, while Nifty Smallcap100 was unchanged during the week. It gained 1.34 per cent at the close.On the sectoral front, all sectors traded with a positive bias. Major contributions came from Nifty Realty, Auto, Healthcare, and Chemicals, while other sectors also posted modest gains. Nifty has 26,200-26,300 as stiff resistance levels while 25,700-25,800 levels will act as support zone, they added.Analysts said markets will likely maintain a cautiously positive bias in near future but remain highly sensitive to global cues. Key drivers going forward include comments from the global central banks for the 2026 policy trajectory. While sentiment remains constructive, near-term volatility may persist amid uncertainty over trade deal timelines and the Indian rupee stability, they added.

Soon, air purifiers at 10,000 govt school classrooms: Delhi Education Minister

Tender floated, says Sood; all 38,000 classrooms to be covered eventually.

New Delhi.(Agency)
Soon, air purifiers will be installed in 10,000 classrooms at government schools to ensure clean air for the students, Delhi Education Minister Ashish Sood announced on Friday, while maintaining that a tender has been floated. Speaking to mediapersons, Sood said the 10,000 air purifiers will be installed in the first phase of the project, and the plan is to extend the facility to all government schools in Delhi.
According to Sood, there are 38,000 classrooms in government schools of Delhi. “We want our children to study smart and also breathe smart air. In the first phase, air purifiers will be installed in 10,000 classrooms. Tenders have been floated today itself,” he said. “The objective is to ensure that air pollution does not adversely affect children’s health or education,” he added.
According to Unified District Information System for Education portal, under the

Union Ministry of Education, there are 5,556 recognised schools in the Capital with an approximate enrolment of more than 46.29 lakh students. Of them, at least 48.25% are government and government-aided schools, with an enrolment rate of 41.61%, as per data from 2022-23. Sources said there are 1,047 government and government-aided schools in Delhi.
“Pollution in Delhi is not seasonal, but the result of years of policy failures,” Sood said, holding the previous AAP government responsible for the current situation.
Citing a recently tabled CAG report, Sood said that in 2017-18, 30% of Air Quality Index monitoring stations were deliberately installed in green areas to conceal actual pollution levels.

He alleged that campaigns such as ‘Odd-Even’ or ‘Gaadi On, Gaadi Off’ were “PR exercises” whose effectiveness had been



questioned by the Delhi Pollution Control Committee and courts. “We are not those who flaunt IIT degrees and do campaigns like Odd-Even or Gaadi On, Gaadi Off

campaign. We are tackling the issue of pollution through long-term administrative measures,” he said, taking a dig at the previous AAP government.
The Odd-Even scheme, first introduced by AAP under then chief minister Arvind Kejriwal, was implemented twice in 2016, from January 1 to 15 and again from April 15 to 30. The scheme aimed to curb vehicular pollution by restricting the movement of private vehicles based on the last digit of their registration numbers.
Sood also said Delhi is surrounded by states, and the weather conditions there determine the weather here. “We are committed towards the issue of eradicating pollution. I want to assure the people of Delhi that we are taking all possible steps, which will show

their results on the ground very soon,” he added. “From October 11, the use of recycled construction and demolition material has been made mandatory in construction works,” Sood said, maintaining that payments for civil works will not be released without compliance.
“The Bhalswa landfill is targeted for complete remediation by September 2026, and a tender has been issued for the disposal of 18 lakh metric tonnes of waste. Biogas plants have been commissioned at the Nangli Sakrawati and Ghoga dairies for scientific disposal of dairy waste,” he said.
The minister, who also holds the urban development portfolio, said the Public Works Department, using the environment cess, will also procure mechanical road sweepers for each Assembly constituency. He added that Rs 175 crore has been released to strengthen municipal bodies, with an additional Rs 500 crore under process.

Day 2 of enforcement drive in Delhi: 419 vehicles turned away at borders for flouting BS-VI norms, 374 fined

New Delhi.(Agency)
The second day of Delhi government’s campaign against non BS-VI compliant private vehicles witnessed 419 cars being turned away from the borders for flouting norms, the traffic police said on Friday, adding that 374 cars were penalised. Overall, 5,037 cars were checked at the borders. On Thursday, 289 challans were issued to vehicles for flouting BS-VI norms. While 2,768 vehicles were checked at the borders, 460 were ordered to return after being found non-compliant.
In all, 2,986 challans were issued across the Capital on Thursday to vehicles that did not have a valid pollution under control certificate (PUC) while 463 light motor vehicles were penalised for flouting BS-VI norms. Just like Wednesday, Western range of Delhi dominated the PUC challan numbers, and New Delhi recorded the lowest, with 881 and 357 challans issued, respectively.
On Wednesday, 2,743 challans were issued to vehicles by the traffic police, including at borders, for not having a valid PUC. Additionally, while the Transport department had issued 316 challans, 687 were issued through the Automatic Number Plate Recognition (ANPR) system, with the total coming to 3,746.
As per data shared by Delhi Police, 13,434 PUC challans have been issued by the traffic police due to GRAP Stage 4 violations inside the Capital. Environment Minister Manjinder Singh Sirsa, meanwhile, said that enforcement teams have issued 11,776 challans against polluting and non-compliant BS-VI vehicles over the 24-hour period, starting at around 7 pm on Thursday.

Month after jewellery worth over Rs 1 crore stolen from parked car in Delhi’s Karol Bagh, member of interstate gang arrested

New Delhi.(Agency)
More than a month after jewellery worth over Rs 1 crore was stolen from a car parked in New Delhi’s Karol Bagh, a member of an interstate gang has been arrested in the theft case, police said on Friday. The accused has been identified as T Sarath Kumar (31), a resident of Tamil Nadu. Jewellery valued at Rs 35 lakh has been recovered from his possession, officers added.
The robbery took place on November 14 after Shubham Kotawala, a jewellery trader, had collected 62 pieces of gold and diamond jewellery along with grading certificates from the International Gemological Institute (IGI) laboratory in Karol Bagh following the certification process.
Police said Kotawala allegedly kept the jewellery in a bag inside his car and stepped out briefly to attend to some urgent work at a nearby shop. When he returned, he found a window of the vehicle broken and the bag missing. Based on his complaint, an FIR was registered at Karol Bagh police station under Section 305 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).
A team of officers scanned footage from nearly 90 to 100 CCTV cameras installed in and around the crime scene and on roads leading to the area, and questioned several known offenders involved in similar cases.
Police said the investigation eventually pointed to a Trichy-based gang known for targeting vehicles parked near jewellery markets by breaking window panes. The team zeroed in on a suspect, Sarath Kumar, after gathering intelligence and tracking his movements in Delhi through technical surveillance.
A resident of Tiruchirappalli in Tamil Nadu, Kumar was apprehended by a team of the Anti-Extortion and Kidnapping Cell of the Crime Branch on December 15 near the Nizamuddin Railway Station following a detailed investigation and technical surveillance, police said.

AAP MCD bypoll candidate alleges tampering of votes in Ashok Vihar ward, moves Delhi court

After hearing the petition, Principal District and Sessions Judge Nisha Sahay Saxena of the Rohini court issued notice and listed the matter for December 24.

New Delhi.(Agency)
Seema Goyal, the Aam Aadmi Party’s (AAP) candidate in one of the 12 wards in the Municipal Corporation of Delhi (MCD) where bypolls were held in November, has moved a Delhi court alleging “tampering of votes”. After hearing the petition, Principal District and Sessions Judge Nisha Sahay Saxena of the Rohini court issued notice and listed the matter for December 24. Goyal had moved a petition challenging the results of the MCD bye-elections of the Ashok Vihar ward. She had claimed that 801 voters had been “erroneously” added in the A-Block polling area. She also claimed that two polling stations “located outside the jurisdictional boundary” had been “unlawfully” included in the electoral roll.

“The purported margin of victory is shown as 405 votes. This result is highly improbable, inconsistent with



the earlier count, and indicative of manipulation, wrongful acceptance of invalid votes, wrongful rejection of valid votes, and possibly unlawful addition of ballots from the misallocated polling areas, including the areas illegally added from Ward

64 and the two misallocated polling stations listed above,” the petition claimed.
It added, “During the counting process, a highly suspicious, unexplained and prima facie fraudulent reversal of the election result occurred. After completion of all 10 out of 10 rounds of counting, the petitioner, Seema Goyal, was leading by 179 votes. However, after an unexplained delay and after certain counting officials moved to an inner enclosure, suddenly and unexpectedly the Respondent No. 1 Smt. Veena Asija (BJP) was declared as the purported Returned Candidate.” In her petition, Goyal also stated that a written complaint had been lodged with the Returning Officer, requesting immediate intervention but no action was taken.

In Supreme Court, lawyer alleges sexual assault, illegal detention by police in Noida

New Delhi.(Agency)
The Supreme Court on Friday sought the response of the Centre and the Uttar Pradesh Police on a plea moved by a woman advocate who alleged that she was sexually assaulted, molested, threatened with sexual violence and wrongfully detained when she visited the Sector 126 police station in Noida to assist a client to file a complaint.
A bench of Justices Vikram Nath and N V Anjaria also took note of allegations that the CCTV cameras in the police station were switched off during the period and directed the Gautam Buddha Nagar police commissioner to make sure that the footage is not

deleted but is kept in a sealed cover.
Appearing for the petitioner, senior advocate Vikas Singh said, “This is a very gross case happening right around Delhi. If it is happening in Noida, just imagine the plight of the entire country.”
The bench, however, asked why the lawyer had not approached the Allahabad High Court instead as the matter pertains to UP. “We are conscious you live in Noida and the SC is more convenient. But that’s the only ground for filing under Article 32?” the court asked.
Article 32 of the Constitution grants every individual the right to move the SC for the enforcement of their

fundamental rights.
Justice Nath remarked, “If we start entertaining all this, then all over Delhi... will start to come to the Supreme Court only.” Singh agreed the case may be transferred



to the HC. “Let your lordships transfer it then. In the meantime, direct them to keep the CCTV. Otherwise all the evidence will be destroyed.”
Singh then sought to remind that the bench was considering a suo motu

matter in relation to absence of functioning CCTV cameras in police stations in Rajasthan. “...This may be made a test case. This should be a message for the entire country. This kind of treatment to a lawyer!” he said. Agreeing to take up the plea, the bench said, “Normally, we would not have entertained this case. However, considering the serious allegations made in the petition and the fact that the issue also relates to locking of CCTV cameras and as this bench is monitoring the installation and functioning of CCTV cameras taking up an incident from Rajasthan, we are entertaining this petition.”

Delhi chokes in very poor air

New Delhi.(Agency)
Delhi’s air quality remained ‘very poor’ for the fourth consecutive day on Friday and is forecast to deteriorate to the ‘severe’ category, while long queues were seen outside pollution under control centres on the second day of the ‘No PUC, No Fuel’ enforcement drive in the city. Official data showed that in the past 24 hours, enforcement teams have issued around 11,776 challans against polluting and non-compliant vehicles as part of an aggressive crackdown on emission sources across Delhi.
Delhi Education Minister Ashish Sood on Friday announced that air purifiers will be installed in 10,000 classrooms to ensure clean air for the students. Addressing a press conference, Education Minister Ashish Sood said that there are 38,000 classrooms, and air purifiers will be installed in them in a phased manner. “We want our children to study smart and also breathe smart air. In the first phase, air purifiers will be installed in 10,000 classrooms. Tenders have been floated today itself,” he added.
Official data shows there are 1,047 Government and Government-aided schools. The minister, who also holds the urban development portfolio, said the Public Works Department, using the environment

cess, will also procure mechanical road sweepers for each of the assembly constituencies. Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa, in a separate press conference, said that Citizen-centric governance continued through swift grievance redressal, with 57 complaints received via 311, Green Delhi App, SAMEER and social media addressed and resolved.
As part of measures to tackle worsening air pollution, authorities here have banned the entry of non-Delhi private vehicles below BS-VI standards and enforced the ‘No PUC, No Fuel’ rule. Official data showed that in the past 24 hours, enforcement teams have issued around 11,776 challans against polluting and non-compliant vehicles as part of an aggressive crackdown on emission sources across Delhi. Even then, the 24-hour average AQI stood in the ‘very poor’ category at 374, marginally higher than 373 recorded a day earlier. Eleven of the 40 monitoring stations in the city have recorded ‘severe’ air quality, while 29 stations recorded AQI in the ‘very poor’ range. Anand Vihar recorded the highest AQI at 430, according to data from the Central Pollution Control Board’s (CPCB) SAMEER app.

Sirsa said the Government has adopted a multi-sector strategy combining enforcement, dust control, waste management, and vehicle regulation, which has led to a notable improvement in AQI levels compared to previous winters.

As part of the anti-pollution drive, 5,037 vehicles were checked at the national Capital’s border points between 8 pm on



Thursday and 8 am on Friday to see if they met BS-VI norms. As many as 419 vehicles were returned, and 374 were prosecuted. Around 2,800 vehicles were identified without valid PUC certificates between 6 am on Thursday and 6 am on Friday, a senior

Transport Department official said. Meanwhile, nearly one lakh pollution-related complaints have been registered with multiple civic and enforcement agencies in Delhi over the past five years, according to official data. A total of 99,435 pollution-related complaints were received till 11 am on December 18 this year, of which 86,984 were resolved, while 12,451 remain pending across various departments, according to data from the Green Delhi App compiled by the Delhi Pollution Control Committee (DPCC).
A day after pollution-under-control (PUC) certificates were made mandatory for refuelling at petrol pumps, commuter awareness appeared to have improved, with many people producing the required documents without being asked. Nischal Singhania, the president of the Delhi Petrol Dealers’ Association, said that queues at PUC certification centres remained unchanged, while fuel sales had taken a hit in some border areas. “Earlier, there was uncertainty about how long the ‘No PUC, No Fuel’ rule would continue. Now, it is clear that it will remain in force till GRAP-IV is in place. Sales have dipped in border areas. Pump owners in Badarpur reported a decline yesterday, and the trend has continued,” he said.

NEWS BOX

US tech enabled China’s surveillance empire. Now Tibetan refugees in Nepal are paying the price

KATHMANDU. (Agency)
The white dome of Boudhanath rises like a silent guardian over the chaotic sprawl of Nepal’s capital, Kathmandu, crowned by a golden spire that pierces the sky. Painted on each of the spire’s four sides are the benevolent eyes of the Buddha—wide, calm, and unblinking—said to see all that unfolds below. Those eyes have served as a symbol of sanctuary for generations of Tibetans fleeing the Chinese crackdown in their homeland. But today, Tibetan refugees are also watched by far more malevolent eyes: Thousands of CCTV cameras from China, perched on street corners and rooftops to monitor every movement below. This intense surveillance has stifled the once-vibrant Free Tibet movement that had resonated around the world.Nepal is just one of at least 150 countries to which Chinese companies are supplying surveillance technology, from cameras in Vietnam to censorship firewalls in Pakistan to citywide monitoring systems in Kenya. This technology is now a key part of China’s push for global influence, as it provides cash-strapped governments cost-effective, if invasive, forms of policing—turning algorithms and data into a force multiplier for control. The irony at the heart of this digital authoritarianism is that the surveillance tools China exports are based on technology developed in its greatest rival, the United States, despite warnings that Chinese firms would buy, copy or outright steal American designs, an investigation by The Associated Press has found.

Brazilian judge allows ex-President Bolsonaro to leave prison for hernia surgery

SAO PAULO .(Agency)
Brazil’s former President Jair Bolsonaro, who has been serving a 27-year prison sentence for an attempted coup since November, was granted permission on Friday to leave prison for a hernia surgery. The date of the surgery has not been announced.Brazilian Supreme Court Justice Alexandre de Moraes gave the far-right leader the go-ahead after federal police doctors confirmed he needs the procedure.Doctors say Bolsonaro’s hernia affects both of his groins and causes him pain. The former Brazilian president, in power between 2019 and 2022, has gone through several other surgeries since he was stabbed in the abdomen during a campaign rally in 2018.De Moraes, who oversaw Bolsonaro’s coup trial and sentenced him to prison, denied the former president’s request for house arrest after he leaves the hospital.Bolsonaro does not have any contact with the few other inmates at the federal police headquarters in the capital of Brasilia, where he is held and where his 12-square-meter room has a bed, a private bathroom, air conditioning, a TV set and a desk, according to authorities. He has free access to his doctors and lawyers, but other visitors have to get their access approved by the Supreme Court.The former president and several of his allies were convicted by a panel of Supreme Court justices for attempting to overthrow Brazil’s democracy following his 2022 election defeat. The plot included plans to kill President Luiz Inácio Lula da Silva, Vice President Geraldo Alckmin and de Moraes. There was also a plan to encourage an insurrection in early 2023.The former president was also convicted on charges that include leading an armed criminal organization and attempting the violent abolition of the democratic rule of law.

Russian Strike Kills 7 In Ukraine's Coastal Odesa Region

Kyiv . (Agency)
A Russian ballistic missile strike killed seven and wounded 15 in Ukraine’s Black Sea Odesa region, a local governor said Friday, adding that the attack targeted port infrastructure. Moscow has stepped up barrages on the important coastal region in recent weeks after President Vladimir Putin threatened retaliation for a slew of Ukrainian strikes on tankers carrying Russian oil.



"The enemy struck the port infrastructure of Odesa region -- seven dead, fifteen wounded," Odesa regional governor Oleg Kiper said on social media. According to him, "the strike caused a fire in a parking lot of trucks."In recent weeks, Russia has pummelled Odesa’s logistics and energy infrastructure, hitting a bridge on the border with Moldova and cutting electricity and heating to hundreds of thousands of people in freezing temperatures. The attacks also damaged foreign-flagged civil vessels in regional ports. Earlier on Friday, Ukraine said it had hit another of Moscow’s sanctions-busting "shadow fleet" tankers in neutral waters of the Mediterranean Sea, its first strike in the sea in the nearly four-year war. Kyiv also struck similar vessels in the Black Sea earlier this month.

150 computers stolen, food looted: How mob vandalised Bangladesh media houses

world . (Agency)
Mobs in Bangladesh launched coordinated attacks on the offices of The Daily Star and Prothom Alo in Dhaka early on Friday night, looting valuables, vandalising buildings and trapping journalists inside for hours. At least 150 computers and other electronic equipment were stolen, and office canteens and files were ransacked. **DEATH OF JULY UPRISING FRONTLINER**
The attacks came hours after news of the death of Sharif Osman Hadi, a July uprising activist and February election aspirant from Dhaka, who succumbed to gunshot injuries in Singapore. Protesters accused the newspapers of fomenting unrest and being aligned with political interests, claims rejected by both media houses. **THE DAILY STAR UNDER SIEGE**
At The Daily Star’s Kazi Nazrul Islam Avenue office, attackers forced entry around midnight. They smashed furniture and glass doors, destroyed computers,

cameras and hard drives, tore down posters of martyrs Abu Sayed and Mir Mahfuzur Rahman Mugdho, and set fire to multiple floors.Flames and thick smoke forced 28 journalists and staff to take shelter on the rooftop for hours. Investigative journalist Zyma Islam posted on Facebook, "I can't breathe anymore. There's too much smoke. I'm inside. You are killing me." Firefighters, police and army personnel rescued the trapped staff around 5 am.The office suffered severe damage, with electricity, water and gas cut off. The Daily Star was unable to publish its print edition for the first time in its 34-year history. **PROTHOM ALO TARGETED SIMULTANEOUSLY**
At Prothom Alo’s Karwan Bazar headquarters, attackers began their assault around 11.15 pm, initially blocked by police. The mob regrouped and launched a full-scale attack, breaking windows, furniture, computers, CCTV cameras, fire

safety systems and cash lockers. The ground to second floors were gutted, and the building’s OTT platform Chorki sustained major damage.



Employees were forced to flee, with one jumping from the roof to a neighbouring building and sustaining serious injuries. The newspaper could not publish its Friday edition for the first time in its 27-year history, and online operations were suspended for nearly 17 hours.

Fire services were delayed as protesters blocked access. Two firefighters, Md Alamgir and Md Shaful Alam, were electrocuted and hospitalised. Police, army and civic leaders, including Nurul Kabir and Shahidul Alam, intervened to secure the area, eventually allowing safe evacuation. **WIDER ATTACKS**
The violence extended beyond the media houses. In Dhanmondi, a mob attacked Chhayanaut Bhaban, vandalising musical instruments, artworks and offices. Parts of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’s residence in Dhanmondi-32 were demolished using excavators. The Bangladesh Udichi Shilpigoshthi office on Tophkhana Road was set on fire.Protests spread to Chattogram, Rajshahi, Uttara and other areas, targeting political and cultural institutions. Police detained 10 people in Chattogram after protesters pelted stones at the Assistant Indian High Commission.

Why H-1B is being used to hire teachers in US

WORLD . (Agency)
A proposal originating in the Trump administration to sharply increase the cost of hiring foreign workers is once again stirring debate in California, as school districts warn it could deepen an already severe teacher shortage. The plan seeks to impose a \$100,000 fee on certain H-1B visa hires, a move education officials say threatens one of the few remaining pipelines for filling hard-to-staff classrooms. States like California are fighting back by suing the administration of President Donald Trump.That US school districts were using the H-1B programme, long associated with the tech industry, to hire foreign teachers came to light with a revelation from California's Department of Education. Data from the the California Commission on Teacher Credentialing shows that more than 300 H-1B applications were submitted in the 2023-24 academic year, double the number recorded two years earlier, according to The Los Angeles Times. Supporters aligned with the MAGA movement argue that the H-1B programme has drifted away from its

original intent and is increasingly being used to fill routine teaching roles that could otherwise go to American educators. Since September, employers have been required to



account for the proposed fee in addition to existing H-1B costs, adding financial pressure on public school systems already struggling with tight budgets.California school districts have increasingly turned to H-1B teachers as staffing shortages worsen. These 300 H-1B applications were concentrated largely in dual language instruction and special education. In 2025, over 32,000 classrooms in California were staffed by out-of-field

teachers, while 10,000 teaching positions remained unfilled, according to the the California Teacher's Association.Teachers affected by the visa system have voiced frustration. A physical education teacher on a J-1 visa told the Los Angeles Times that "Everybody says here that they need teachers in California but they don't want to do anything to [help us stay] here." An H-1B elementary school teacher added, "I feel like it's a form of discrimination to impose \$100,000 fee for teachers."The shortage of teachers, however, extends far beyond California. According to a study by the Learning Policy Institute, all 50 US states and Washington DC are grappling with significant staffing shortfalls. The result has been widespread understaffed classrooms and teachers being required to teach subjects for which they are not trained. As visa curbs tighten and costs rise, school districts warn that one of the few available stopgap measures is being restricted.

Young conservative women in US find home in Turning Point with Charlie Kirk's widow at the helm

PROVIDENCE .(Agency)
PHOENIX: Camdyn Glover used to be a quiet conservative. She worried what her teachers would think or if she would lose friends over her convictions. But she said something changed when Charlie Kirk was assassinated in September, and she started crying in her classroom at Indiana University while other students cheered and clapped.“We can’t be silenced,” Glover decided. Now she’s visiting Phoenix with her parents and brothers for this year’s Turning Point USA conference, the first to take place since Kirk’s death. Although the organization became a political phenomenon with its masculine appeals to college men, it’s also been expanding outreach to young women like Glover.The shift is poised to accelerate now that Turning Point is led by Erika Kirk, Charlie’s widow, who has embraced her new role at the helm of a conservative juggernaut with chapters across the country.If

successful, the organization that helped return President Donald Trump to the White House could narrow a gender divide that has been a persistent challenge for Republicans. Turning Point offers a blend of traditional values, such as encouraging women to prioritize marriage over careers, and health trends that have become popular online.On Friday, young women lined up for selfies with wellness influencer Alex Clark while vendors sold health products and Trump merchandise. One of Clark’s fans had a “Make America Pro-Life Again” hat and “MAHA red” lipgloss, a reference to the “Make America Healthy Again” agenda pushed by Robert F. Kennedy Jr. Another attendee sported a “grass-fed conservative” pin on her lanyard. Glover, 18, said discovering Turning Point in high school gave her an appreciation for dialogue when she felt like an outcast for her beliefs, such as being anti-abortion. At her first

conference, she feels like she’s found a political and cultural home for herself. “They want to promote a strong independent woman who does hold these values and can go stand up for herself,” she said. “But it’s also OK to do it in heels, put some makeup on, wear a dress.”If Erika can do it, I can do it’One of Glover’s classmates, Stella Ross, said she stumbled upon Charlie Kirk on TikTok in the months before the last presidential election.She already felt like her perspectives were being treated differently on campus and thought she was receiving unfairly low grades in her political science classes. A devout Catholic, Ross said she was inspired by how Charlie Kirk wasn’t afraid to weave his evangelical faith into his political arguments.She also noticed how many women posted comments of appreciation on Erika Kirk’s videos, and she joined Indiana University’s Turning Point chapter in the same month that Trump won his comeback.



consideration of both said factors that a lenient view has been taken in awarding lesser punishment," a copy of the verdict accessed by Dawn stated.Following the verdict, the counsel of Khan and Bibi said they would challenge the decision before the High Court. In October this year, Imran Khan and Bushra Bibi rejected all charges in the case, calling it fabricated, and a politically driven move aimed at disqualifying him from politics.Imran Khan, who has been in prison since August 2023, is serving a 14-year sentence in a EUR 190 million corruption case and is also facing pending trials under the Anti-Terrorism Act over the May 9, 2023 protests. Bushra Bibi is likewise serving a seven-year sentence in the same corruption case. The latest sentencing comes amid growing criticism of the Pakistan government over alleged mistreatment of Imran Khan in custody, with even the United Nations calling for his immediate release from solitary confinement.

Sri Lanka's tea workers struggle in poverty. Flooding cost many their lives

WASHINGTON. (Agency)
CRAIGHEAD ESTATE. Arumugam Manikavalli, awakened by ferocious rain and rumbling earth, fled her home for the safety of a nearby temple on the tea estate where she works.That same November evening, tea worker Kumaran Elumugam’s small home was crushed by a landslide, killing six family members.He survived only because he was away, at work, along with a daughter. “My wife, son-in-law, daughter, mother-in-law, two grandsons are all dead,” Elumugam lamented. “The small one (granddaughter) is still under the mud.”Elumugum and Manikavalli were among the fortunate to reach safety as heavy rains from Cyclone Ditwah led to floods and landslides across the South Asian island nation, killing more than 640 people and leaving more than a hundred missing.Multiple villages were submerged by landslides that left behind a rubble of cement, wood and roofing. In one area, the wreckage was dotted with clothing,

schoolbooks, toys and a sports trophy. Among the hardest hit were the hilly regions in the island’s center and the tea plantation workers who live there. Many occupied primitive, 150-year-old structures that were swept away in landslides and flooding. Social workers said these plantation workers, already living in extremely distressed conditions, are now in an even more desperate situation.Poorly paid tea plantation workers worst hit by the disasterMost tea plantation workers in Sri Lanka belong to the Malaiyaha Tamil ethnic group. Descendants of Tamil indentured laborers who were brought to work from southern India by British colonists more than 200 years ago, over 1 million people belong to this community, the fourth-largest ethnic group on the island.Sri Lanka grows some of the world’s finest tea, bringing billions of dollars into the country. But most Tamils in the hill regions earn well below the minimum wage of 1,200 rupees (\$4) per day, with

little or no access to education, health care or good jobs.A report by the American Institute for Sri Lankan Studies said most tea plantation workers own no land or homes and are living in colonial-era



working quarters barely bigger than 100 square feet but accommodating as many as eight family members. Multiple houses share bathrooms or have no sanitary facilities.Many of the tea plantations, on flatter ground, were unaffected by the cyclone while the workers' homes, which

were closer to mountain slopes, were destroyed, said Melanie Gunathilaka, a Colombo-based climate activist and researcher.“The settlements were in much more dangerous areas," she said. “This shows the amount of value placed on the lives of these people.”The Planters Association of Ceylon, the association for Sri Lanka’s tea companies and estates, didn’t immediately respond to a request for comment.The government said more than 100,000 houses were destroyed or damaged across Sri Lanka. It has promised compensation packages to rebuild houses or to find safer lands and build new houses. Sundaralingam Pradeep, Sri Lanka’s deputy minister for plantations and community infrastructure, told The Associated Press that the government is negotiating with the tea companies to identify lands to build homes for all those affected by the disaster, including retirees still living in company line houses.

Ravindra Jadeja, Shikhar Dhawan, and Siddharth Trivedi forced their way into the public consciousness, reminding everyone that the league wasn't just about established greatness. The IPL's now-familiar mantra – where talent meets opportunity – took shape almost immediately. It became more than a parade of superstars, offering young, uncapped players a platform to seize the grandest stage. Suddenly, cricket turned into a financially viable pursuit for thousands of aspirants. One breakout season, one raised paddle at an auction, could change a life forever. Just ask Prashant Veer. Over the years, uncapped players have routinely made headlines on auction day. With the rise of state-level T20 leagues, scouts are now spoilt for choice, stumbling upon hard-to-miss talent across the country. A decade ago, teams like Mumbai Indians were praised for deep scouting that unearthed players such as Pandya brothers and Jasprit Bumrah. Today, that approach is no longer a luxury. It's a necessity.

Did Rashmika Mandanna

And Vijay Deverakonda Get Secretly Married? Here's The Truth Behind



Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda have once again hit the headlines. Speculations around the couple being secretly married recently took over social media after a series of pictures featuring the two actors went viral. The photos showed Rashmika and Vijay dressed in traditional wedding ensembles, posing with Mahesh Babu and Namrata Shirodkar on the stage. The pictures left fans curious, and many wondered whether Rashmika and Vijay had secretly tied the knot. However, the photos turned out to be AI-generated, and the actors are not married.

Truth Behind Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda's Viral Wedding Pics

The photos shared by Instagram user Gunti Srikala Nagaraju showed Rashmika and Vijay in traditional wedding outfits with garlands, while Mahesh Babu and Namrata Shirodkar posed next to them on the stage. The stage was decorated with flowers while the board behind them read, "Vijay and Rashmika." The pictures went viral on social media, with many fans wondering whether they tied the knot in a private ceremony. The photos, however, are AI-generated.

Vijay and Rashmika reportedly got engaged in October. Sources close to the actors told recently that their engagement was held on October 3, 2025, at Vijay's Hyderabad residence. The ceremony was described as "intimate and elegant," attended only by family members and a handful of close friends. As per reports, Rashmika and Vijay are likely to tie the knot on February 26, 2026, at a luxurious palace in Udaipur, Rajasthan. Though the couple has yet to officially confirm the news, the alleged venue and date sent fans into a frenzy. In October, Rashmika shared a cute video of her dog, Aura, and fans were quick to spot a sparkling ring on her finger. Around the same time, Vijay was photographed at Sri Sathya Sai Baba Maha Samadhi wearing what looked like a matching band.

Meanwhile, in November, Vijay was seen kissing Rashmika's hand at the success party of her film 'The Girlfriend'. Fans gushed over their chemistry, and the video went viral in no time. The two first met on the sets of Geetha Govindam (2018) and later reunited for Dear Comrade (2019).



Shalin Bhanot Hints At Second Marriage In 2026, Says Family Wants Him To 'Stop Being Single'



Television actor Shalin Bhanot has finally addressed the buzz around his personal life and the reports suggesting that he may get married again in 2026. Speaking candidly, the actor admitted that while marriage is very much on the cards, the decision is being influenced largely by his close circle.

Reacting to the speculation, Shalin shared that his friends and relatives have been persistently nudging him to settle down. "Everyone around me is married or in a relationship. I am literally the only one who is single. My friends and family don't want me to be alone and are manifesting that I should get married next year," he said, adding that the constant pressure has been emotionally taxing.

Despite the chatter, Shalin made it clear that when the time comes, the moment will be intimate and deeply personal. "My parents are like gods to me. Whenever that special moment happens, I will celebrate it only with them," he concluded.

Shalin Bhanot And Tina Datta's Tumultuous Bigg Boss 16 Equation

Shalin Bhanot's personal life often came under scrutiny during his stint on Bigg Boss 16, largely due to his complicated relationship with co-contestant Tina Datta. Their on-again, off-again bond quickly became one of the most talked-about aspects of the season.

While Shalin was vocal about his feelings for Tina, she repeatedly maintained that they were only friends, despite sharing several close moments on the show. Their dynamic drew heavy criticism from netizens, many of whom accused the duo of manufacturing a romance for attention and votes.

As the season progressed, the equation deteriorated rapidly. What began as affection turned into bitterness, eventually leading to the two cutting off communication entirely and engaging in frequent, heated arguments inside the house.

A Look Back At Shalin Bhanot's Divorce From Dalljiet Kaur

Before his Bigg Boss journey, Shalin Bhanot's marriage to actress Dalljiet Kaur had also made headlines. The two tied the knot in 2009 and welcomed their son, Jaydon, in 2014.

Farah Khan's Proud Parent Moment As Triplets Secure Spots In US Universities



Farah Khan and her husband, Shirish Kunder's triplets, Anya, Diva, and Czar, are already heading to universities. The filmmaker-choreographer who has been garnering immense attention for her YouTube vlogs, courtesy of witty conversations with her cook, Dilip, has often spoken about choosing the platform to back her kids' studies. Now, the doting mommy received an adorable gift to mark their new journey.

On her Instagram stories, Farah Khan gave a sneak peek of the adorable cupcakes to mark a significant milestone in her kids' lives. In the picture, we can see a box full of cupcakes, each decorated with the university's logo, name, and design, which the three children are set to attend. The universities include NYU in the US, Babson, and Emory.

More About Farah Khan's Kids' Higher Education

Atop the thoughtful gift from her friend, the Om Shanti Om director wrote, "This is the sweetest... thank u @poojaadhoor...n congratulations to all our kids...@_daisclassof2026#hattrick."

Soon, the update caught the attention of her fans, who shared the photo on Reddit, leaving others nostalgic about the passage of time. Diva is off to Babson College, a private business school in Wellesley, with majors in entrepreneurship and finance. On the other hand, Anya will attend NYU (New York University), where she will specialise in economics and data science. Meanwhile, Farah's son, Czar, is heading to Emory, a private research university in Atlanta, Georgia. As per the posts, he will pursue Artificial Intelligence in Business.

Fans' React To Farah Khan's Kids Growing Up

Social media users expressed surprise at how grown-up the trio looks now. A fan said, "I still remember when she had triplets and when they were babies. Wow, how time flies! Can't believe they are college goers now!" Echoing the same emotion, a user mentioned, "Feeling old." Someone added, "Time flies. Abhi toh paida hue the, congrats to them!" Meanwhile, a user commented, "Paying for 3 kids' college at the same time sounds like... a lot." While another shared, "Wow, imagine having to pay 3 college fees at the same time! She started her YouTube channel at the right time. Jokes apart, it's so nice to see her kids going to college."

When Farah Khan Talked About Her Challenging Pregnancy

The filmmaker has often admitted that she started her YouTube journey to finance her children's education. Recently, when Farah appeared on Twinkle Khanna and Kajol's show Two Much, she shared how YouTube helped her meet the various demands of her kids' studies.

Mrs Deshpande Review

Madhuri Dixit

Anchors Nagesh Kukunoor's Tense, Layered Crime Thriller

Madhuri Dixit carries a kind of concentrated intensity that feels almost royal, as if certain characters arrive in her body already crowned. Across decades and drastically different worlds, she has proven a rare elasticity of presence, the ability to slip into a role and make it look less like performance and more like revelation. Whether she was Pallavi Patel in Maja Ma, a closeted housewife standing at the trembling edge of self-acceptance, Bahaar Begum in Kalank,



a courtesan draped in grace and quiet wounds, or the quintessentially sanskari Nisha Choudhury in Hum Aapke Hai Koun, Dixit has consistently made the emotional temperature of a scene rise simply by inhabiting it. And after watching Mrs Deshpande, Nagesh Kukunoor's Indian adaptation of the French mini-series La Mante, it feels safe to say she has hit it out of the park yet again, in a clever, if imperfect, thriller that peels itself open like

survival in Yakutsk: layered upon layered, and the more you strip away, the more you realise you are not just watching, you are sinking.

The premise arrives with the clean chill of a headline. A new string of murders replicates the exact modus operandi of killings committed twenty-five years ago by an imprisoned serial killer. With no room for coincidence, law enforcement relocates the original murderer, Mrs Deshpande, to a safehouse to help catch the emerging copycat. Madhuri Dixit

plays Mrs Deshpande with a restraint that feels more terrifying than theatrics. She agrees to cooperate, but on one condition: she will work only with Inspector Tejas Phadke, played by Siddharth Chandekar, unaware that she is his mother. The hook is blunt, unsettling, and rich with psychological promise, because it makes the case procedural on the surface but deeply personal at its core. The first episode wastes no time easing you in. A murder unfolds within minutes, swift and unsettling in its specificity. An actor

is strangled with a thin neon green rope, a visual detail that burns itself into memory like a warning sign. The killer places one of the actor's trophies in his hands, then glues his eyes so they cannot shut, forcing the dead to stare. When senior IPS officer Arun Khatri, played by Priyanshu Chatterjee, arrives, a déjà vu settles over him like fog. He has seen this choreography before.

